जनता के गोठ

Website- https://www.jantakegoth.com

● वर्ष -01 ● अंक- 313 ● रायपुर, बुधवार 04 नवम्बर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ- 12 ● मूल्य- 2 रुपया ● संपादक- शुभम वर्मा ● PRGI Reg No : CTBIL/25/A1787

पहला कॉलम

नोनी जिले में भीषण गोलीबारी में 3 कुकी ग्राम स्वयं सेवकों की मौत

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं से तनाव गहरा गया है। राज्य के नोनी जिले में एक सुदूर पहाड़ी गांव के जंगलों में दो सशस्त्र गुटों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। दूसरी तरफ, कांगपोकपी जिले से कई दिनों से लापता चल रहे दो युवकों के शव सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए गए हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में भारी तनाव फैल गया है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गोलीबारी की यह खूनी वारदात शनिवार सुबह नोनी जिले के अंतर्गत आते केकडू नागा गांव के नजदीकी पहाड़ी इलाके में शुरू हुई।

ट्रेलर और कार के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में नेशनल हाईवे-28 पर एक मारुति ओमनी कार और भारी ट्रेलर के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं, बाराबंकी में तेज रफ्तार एसयूवी ने दो बाइकों को रौंद दिया, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई। इसके अलावा मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो डबल डेकर बसों और कैंटर की भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एनएच-28 पर थरुआडीह के समीप देर रात यह दिल दहला देने वाली दुर्घटना घटी। मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी लोग रिश्तेदारी में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होकर वापस अपने घर लौट रहे थे।

शराब माफिया का आतंक, ट्रक से थाना इंचार्ज को कुचल

देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले में शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। हरदा से गुजरात जा रहे संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रही पुलिस टीम ट्रक को रोकने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान ट्रक चालक ने कथित रूप से वाहन चढ़ा दिया, जिसमें खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, देवास के एसपी आदित्य मिश्रा ने ट्रक को पकड़ने के लिए पांच से अधिक पुलिस टीमें बनाई थीं। इनमें कन्नौद, सतवास और खातेगांव के थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा ट्रक हरदा की ओर से आ रहा है और इंदौर होते हुए गुजरात जाने वाला है। पुलिस टीमें ट्रक का पीछा कर रही थीं और आगे नाकाबंदी भी की गई थी। इसी दौरान हरदा-नेमावर हाईवे पर ट्रक चालक पानी पीने के लिए रुका।खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी उसे पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को ट्रक से नीचे उतरने के लिए कहा। इसी दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। बताया जा रहा है कि चालक ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की।

इसी दौरान दिलीप पुरी नीचे गिर गए और ट्रक का पिछला पहिया उनके ऊपर से निकल गया।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 36 विभूतियों एवं संस्थाओं को राज्य अलंकरण से किया सम्मानित

■ राज्योत्सव के समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को मिला राज्य का प्रतिष्ठित सम्मान

रायपुर/ संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, कृषि, समाजसेवा, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सहकारिता, श्रम, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान किया गया। राज्य अलंकरण से सम्मानित विभूतियों एवं संस्थाओं का विवरण शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए धमतरी जिले के श्री डुमन लाल ध्रुव को प्रदान किया गया। यति यतनलाल सम्मान अहिंसा एवं गोरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दुर्ग जिले के विश्व गीता धेनू गोविन्द पक्षी सेवा धाम, कुम्हारी को प्रदान किया गया। गुण्डाधूर सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोरबा जिले की सुश्री संजू देवी को प्रदान किया गया। मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान एवं जनजागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोक आस्था सेवा संस्थान, गरियाबंद (सुश्री लता नेताम) को प्रदान किया गया। गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कबीरधाम जिले के श्री सुखचंद भास्कर को प्रदान किया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बस्तर जिले की प्राथमिक कुडुक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, चित्रकोट (श्री धनसिंह बघेल) को प्रदान किया गया। हबीब तनवीर सम्मान समकालीन रंगकर्म, छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं अन्य भाषा नाटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रायपुर जिले के डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर को प्रदान किया गया। महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, विशेष रूप से तीरंदाजी के लिए बालोद जिले के श्री टोमन कुमार को खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कबीरधाम जिले के श्री पुन्नीदास भट्ट को प्रदान किया गया। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रायगढ़ जिले के श्री बाबूलाल अग्रवाल को प्रदान किया गया। चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिन्दी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रायपुर जिले के श्री प्रमोद कुमार साहू को प्रदान किया गया। चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिन्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रायपुर जिले के श्री बरुण सखाजी एवं सुश्री रसिका पांडेय को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रायपुर जिले के श्री शिशिर रॉय चौधरी को प्रदान किया गया। धन्वन्तरि सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए धमतरी जिले के डॉ. दिनेश कुमार नाग को प्रदान किया गया। श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बालोद जिले के श्री प्रदीप कुमार सोनी को प्रदान किया गया। राजेश्री महंत वैष्णवदास जी महाराज संस्कृत भाषा पुरस्कार संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रायपुर जिले के डॉ. बहुरन सिंह पटेल को प्रदान किया गया। डॉ. भंवरसिंह पोर्ते आदिवासी सेवा पुरस्कार आदिवासियों की सेवा और आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर (श्री सी. श्रीनिवास यंगम) को प्रदान किया गया। स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बलौदाबाजार जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट कुकुरडीह, सीमेंट वर्क्स, सरकीपार को प्रदान किया गया।



नवा रायपुर को 'पीपल सिटी' बनाने की पहल :अमित शाह ने विकसित भारत संकल्प पार्क का किया गया लोकार्पण

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-16 में विकसित भारत संकल्प पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद अमित शाह ने पार्क में पीपल का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। करीब 16 एकड़ में फैले इस पार्क को पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यहां 2,500 से अधिक पीपल के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रजातियों के 500 से ज्यादा पौधे भी पार्क का हिस्सा हैं। नवा रायपुर को 'पीपल सिटी' के रूप में विकसित करने की योजना के तहत इस पार्क को अहम पहल माना जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल पौधरोपण करना नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना भी है। पार्क के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नवा रायपुर में किया विकसित भारत संकल्प पार्क का लोकार्पण



रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-16 में विकसित भारत संकल्प पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने पार्क परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को चिरस्थायी बनाने और भावी पीढ़ियों तक राष्ट्र निर्माण का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प पार्क का निर्माण किया गया है। यह पार्क विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की परिकल्पना का प्रतीक होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देगा। नवा रायपुर को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस पार्क में अब तक 2,500 से अधिक पीपल और 500 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। यह पार्क नवा रायपुर को 'पीपल सिटी' के रूप में नई पहचान दिलाने के साथ ही शहर की हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।नवा रायपुर को हरित और पर्यावरण अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'ह्रश्वश्चद्यद्व द्बश्ह ह्रद्बद्गश्चद्बद्य' अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधरोपण करना नहीं, बल्कि नागरिकों को पौधों के संरक्षण, संवर्धन और नियमित देखभाल से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देना है। इसी पहल के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प पार्क को पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और सतत विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष का विशेष आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व है। इस अभियान के माध्यम से पीपल के प्रति जनआस्था को प्रकृति संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प पार्क आधुनिक शहरी विकास और प्रकृति के बीच संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगी।

आज रायपुर में स्पेशल कोर्ट में होगी सौरभ की पेशी

महादेव सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर को लेकर रायपुर पहुंची सीबीआई की टीम

नई दिल्ली/ एजेंसी

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को लेकर सीबीआई की टीम लेकर देर शाम रायपुर पहुंची। उसे फ्लाइट श्व6 2307 से दिल्ली से रायपुर लाया गया। वहीं सौरभ को लेकर एयरपोर्ट से सीधे सीबीआई दफ्तर पहुंची। मिल रही जानकारी के अनुसार कल यानी 4 नवंबर को उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि आरोपी को 4 नवंबर 2026 या उससे पहले रायपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद आज सीबीआई की टीम सौरभ को लेकर रायपुर पहुंच रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम 4 बजे के आसपास पहुंचने की उम्मीद। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 एफआईआर जांच के लिए सीबीआई को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने जवाब में कहा कि बचाव पक्ष जिस आदेश का हवाला दे रहा है, वह पुराना आदेश है। एजेंसी के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी नए आदेश के तहत हुई है। जिसमें किसी विशेष जांच एजेंसी का उल्लेख नहीं है।



आपस में टकराये दो हेलीकॉप्टर, एक भारतीय पर्यटक की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में आज बड़ा हेलिकॉप्टर हादसा हुआ। सोलुखुम्बु जिले के फेरेचे हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान दो हेलिकॉप्टर आपस में टकरा गए। इसमें एक भारतीय की मौत की खबर है। सोलुखुम्बु जिला पुलिस के प्रभारी नवीन राजा बुधाथोकी ने बताया कि हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौके पर मौत हुई है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों हेलिकॉप्टर में हादसे के समय कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक फ्रिशटेल एयर और एयर डायनेस्टी के हेलिकॉप्टर टकराए हैं।

सुप्रीम कोर्ट बोला-हर किसी को विरोध का अधिकार

कोई संगठन अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन स्थल पर कब्जा नहीं कर सकता-सुप्रीम

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली में पिछले महीने हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी हर समय कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि किसान, पत्रकार और दूसरे संगठनों को भी विरोध करने का अधिकार है। साथ ही अदालत ने कहा कि, ऐसे आयोजनों के लिए निर्धारित स्थलों की एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर बहस हुई। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि जंतर-मंतर एक अधिसूचित विरोध स्थल है और वहां प्रदर्शनों के खिलाफ उठाई जा रही आपत्तियों पर सवाल उठाया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, विरोध करने का अधिकार सभी को है। इसके लिए एक निर्धारित समय अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। कोई भी समूह किसी विशेष स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। सरकार के शीर्ष वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन की अनुमति केवल एक दिन के लिए दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि संसद तक मार्च भी किया।



पहले पैसा भाई-भजीतावाद पर जाता था

पीएम मोदी बोले-50 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा को पार किया

पीएम नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को महाराष्ट्र दौरे पर रहें। इस दौरान प्रधानमंत्रई मोदी ने पुणे मेट्रो की करीब 21,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में '50 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा को पार किया है। पहले पैसा भाई भजीतावाद पर जाता था। बीजेपी सरकार में पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियां 'गरीबी हटाओ' के नारों और वादों के बीच ही बड़ी हुई हैं। पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी, लेकिन आज भारत जमीन पर गरीबी को परास्त कर रहा है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ गरीबी कम करने वाले सबसे तेज देशों में भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुणे हमेशा से ऐसे विचारों का केंद्र रहा है, जिन्होंने देश और समाज को नई दिशा दी है। आज यह शहर विकसित भारत की नई ऊर्जा को आगे बढ़ा रहा है। आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टार्टअप, नवाचार और विनिर्माण के क्षेत्र में पुणे की अहम भूमिका है। ऐसे में मजबूत मेट्रो कनेक्टिविटी से यहां के विकास को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने करीब 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो



परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी 23 किलोमीटर लंबी मेट्रो की तीसरी लाइन यानी पिंक लाइन का उद्घाटन शामिल है। यह लाइन मान से जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन तक जाएगी और हिंजेवाड़ी के आईटी हब को शिवाजीनगर से जोड़ेगी। इस लाइन की खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह महिला ट्रेन ऑपरेटर करेंगी। साथ ही, इसकी बिजली की करीब 30 प्रतिशत जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने की योजना है। उन्होंने कहा कि देश में पहली मेट्रो 1984 में चली थी, लेकिन इसके बाद के 30 वर्षों में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ। वर्ष 2014 तक देश के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि अगर पुरानी सोच और पुरानी कार्यशैली जारी रहती, तो पुणे में मेट्रो पहुंचने में कई दशक और लग जाते। 2014 में देश में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर करीब 1,400 किलोमीटर हो गया है। पहले पांच शहरों में मेट्रो चलती थी, जबकि अब 26 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि भारत में गरीबी पर वर्ल्ड बैंक ने पिछले दिनों रिपोर्ट जारी की थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 साल में 49.6 ष्टह्र लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। मोदी सरकार की रोजगार और योजनाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी ने इन गरीबों की तकदीर और तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

बस्तर ओलम्पिक में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, कमिश्नर डोमन सिंह ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

बकावंड में खिलाड़ियों से किया संवाद, विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित; सुरक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर, । बस्तर संभाग में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित बस्तर ओलम्पिक के तहत मंगलवार को बकावंड विकासखंड मुख्यालय में विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री डोमन सिंह पहुंचे। उन्होंने विभिन्न खेल स्पर्धाओं का निरीक्षण कर आयोजन स्थल पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया।

कमिश्नर श्री सिंह ने बालक एवं बालिका जूनियर वर्ग की ऊंची कूद स्पर्धा में शामिल प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें आत्मविश्वास एवं समर्पण के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बालिका जूनियर वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में करीतगांव एवं करपावंड की टीमों के बीच हुए मुकाबले के खिलाड़ियों से भी



संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान कमिश्नर ने बालिका जूनियर वर्ग की लंबी कूद एवं गोला फेंक प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम हैं। बस्तर ओलम्पिक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बालिकाओं को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल रहा है।

खिलाड़ियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण करते हुए कमिश्नर श्री डोमन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों की सुविधाओं और सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक खेल स्पर्धा के अनुरूप मैदान और आवश्यक खेल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला खिलाड़ियों के लिए पृथक चेंजिंग रूम तथा खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने आयोजन स्थल पर आवश्यक दवाइयां, एंबुलेंस और चिकित्सा दल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी खिलाड़ी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार मिल सके। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए स्वच्छ पेयजल, जलपान और भोजन की समुचित व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।

कमिश्नर ने सभी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलम्पिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए आयोजन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और खिलाड़ियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत खेल एवं युवा कल्याण समिति के सभापति श्री वनवासी मौर्य, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, एसडीएम श्री अमित बेक, तहसीलदार जागेश्वरी पोयाम, जनपद पंचायत सीईओ श्वेता साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी, बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेलप्रेमी नागरिक उपस्थित रहे।

800 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुई तीर्थ यात्रा



जनता के गोठ/ओंकार साहू बलौदाबाजार। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम उस समय देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 800 से अधिक श्रद्धालु झारखंड स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रस्तावित इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं ने बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा बैजनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। यात्रा के दौरान बैजनाथ धाम के साथ तपोवन एवं अनुकूल ठाकुर आश्रम के भी दर्शन कराए गए। इस यात्रा की खास बात यह रही कि विशेष ट्रेन में सफर के दौरान भी भक्ति की धारा बहती रही। ढोलक, झांझ और मंजीरे की थाप पर श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते नजर आए। ट्रेन में भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा एवं देवी-देवताओं के चित्र स्थापित किए गए थे, जिससे पूरी यात्रा धार्मिक माहौल में संपन्न हुई। 89 वर्षीय वयोवृद्ध तीर्थयात्री केजूराम साहू सहित दिलेश्वर वर्मा, रविन्द्र वर्मा, गौतम पाल, रुखमणी साहू, फूलबाई धृतलहरें, मंजूलता अवस्थी, शारदा भोसले, सरोज देवांगन, रजनी दुबे, वंदना इंगोले, सुवर्णा शर्मा एवं ठगने बारले ने यात्रा को अपने जीवन का यादगार अनुभव बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। यात्रा में भोजन, ठहरने, परिवहन एवं दर्शन की समुचित व्यवस्था रही। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

साहित्य साधना के लिए राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' को कम्मू राष्ट्र गौरव सम्मान-2027

संस्कारधानी रायगढ़ की माटी के गौरव, पूर्व प्राचार्य एवं साहित्यसेवी राज 'राज' की उपलब्धि से साहित्य जगत में हर्ष की लहर

रायगढ़/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी रायगढ़ की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उर्वरा भूमि पर जन्मे श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' शिक्षा, साहित्य, सामाजिक चेतना और रचनात्मक सृजन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हैं। स्वर्गीय श्रीमती सुशीला एवं स्वर्गीय श्री वाई.पी. पाण्डेय (पुलिस अधिकारी) के सुपुत्र राजेन्द्र कुमार पाण्डेय बचपन से ही मेधावी, प्रतिभाशाली एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। अध्ययन-अध्यापन, खेलकूद और साहित्यिक गतिविधियों में उनकी विशेष रुचि रही है। शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवाएँ प्रदान करने के पश्चात वे प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए।

साहित्य के प्रति उनकी सहज अभिरुचि ने समय के साथ एक व्यापक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया। कथा, कहानी, कविता एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में लेखन करते हुए उन्होंने नवोदित रचनाकारों को मंच प्रदान करने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से वर्ष 2021 में सोशल मीडिया के सशक्त माध्यम फेसबुक पर 'राज श्री राष्ट्रीय साहित्य अकादमी' की स्थापना की। उनका यह छोटा-सा प्रयास आज एक विशाल साहित्यिक परिवार का रूप ले चुका है। लगभग 20 हजार साहित्यकारों एवं रचनाकारों से जुड़ा यह आदर्श साहित्यिक समूह नवप्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित करने तथा हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में निरंतर सक्रिय है। अकादमी के माध्यम से काव्य गोष्ठियाँ, साहित्यिक प्रतियोगिताएँ, विशेष पर्वों पर रचनात्मक आयोजन, सम्मान समारोह एवं विविध साहित्यिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। विशेष बात यह है कि अकादमी साहित्यकारों को निःशुल्क मंच उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' का मानना है कि साहित्य केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को संस्कारित करने,



मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने और नई पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने का सशक्त साधन है।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित- उनकी साहित्यिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उपलब्धियों को देखते हुए देश-विदेश की अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जयपुर द्वारा प्रदत्त 'मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान', शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन, नेपाल द्वारा प्रदान की गई मानद उपाधि 'मातृभाषा रत्न', सहकार जगत साहित्यिक सम्मान, नेशनल रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर हेल्थ सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहित्य शिक्षक रत्न सम्मान' एवं 'राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान' प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा 'राष्ट्रीय साहित्य रत्न', 'राष्ट्रीय काव्य शिरोमणि' सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों एवं मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया है। ये सम्मान उनके साहित्यिक अवदान, शिक्षकीय गरिमा, सामाजिक प्रतिबद्धता और निरंतर रचनात्मक सक्रियता के परिचायक हैं।

कम्मू राष्ट्र गौरव सम्मान-2027 के लिए चयनित

इसी गौरवशाली उपलब्धियों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ने जा रही है। देश के प्रतिष्ठित कमलादेवी जनसेवा संस्थान, सीकर द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' का वर्ष 2027 के 'कम्मू राष्ट्र गौरव सम्मान' के लिए चयन किया गया है। यह सम्मान उनके बहुआयामी व्यक्तित्व, साहित्यिक साधना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान तथा समाज के प्रति समर्पित सेवाभाव का महत्वपूर्ण सम्मान माना जा रहा है।

उनके इस चयन से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, शुभचिंतकों एवं राज श्री राष्ट्रीय साहित्य अकादमी परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों ने इसे न केवल राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' की व्यक्तिगत उपलब्धि, बल्कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने वाला प्रसंग बताया है।

इस अवसर पर श्री पाण्डेय ने सभी सम्मानदाता संस्थाओं, साहित्यकारों, सहयोगियों, शुभचिंतकों एवं अकादमी परिवार के सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उनकी साहित्यिक यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने भविष्य में भी साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और नवोदित रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु निरंतर समर्पित रहने का संकल्प व्यक्त किया।

निस्संदेह, राजेन्द्र कुमार पाण्डेय 'राज' की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची साधना, सकारात्मक सोच और साहित्य के प्रति समर्पण से एक छोटा-सा प्रयास भी हजारों प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का विशाल मंच बन सकता है।

दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू, अब ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए नहीं लगाना पड़ेगा पंडरिया का चक्कर

लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी, विधायक भावना बोहरा ने किया कार्यालय का शुभारंभ; स्थानीय स्तर पर होंगे जमीन और राजस्व संबंधी कार्य



कवर्धा। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत दामापुर में उप तहसील कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय के शुरू होने से दामापुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए पंडरिया तहसील कार्यालय तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

दरअसल, दामापुर क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के बड़े ग्रामीण इलाकों में शामिल है। आसपास के कई गांवों के लोग विभिन्न शासकीय और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दामापुर पर निर्भर रहते हैं। अब तक छोटे-बड़े राजस्व कार्यों के लिए ग्रामीणों को पंडरिया जाना पड़ता था। इससे उन्हें आने-जाने में समय और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्षेत्रवासी लंबे समय से दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे।

ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दामापुर में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब लोगों को जमीन और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही शासकीय कामकाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा तथा उनकी समस्याओं का निराकरण भी सुगम होगा।

विधायक ने इस सौगात के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

बकावंड हाई स्कूल मैदान में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ

जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर किया उद्घाटन, 14 प्रकार के खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ। विकासखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनवारी भद्रे, उपाध्यक्ष तरुण पांडे, जितेंद्र पाणिग्राही, बनवासी मौर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर अगरबत्ती जलाई और तिलक लगाकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद खिलाड़ियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाएं, सरपंच, सचिव एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



आयोजन में स्कूली बच्चों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के तहत खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत कुल 14 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और युवा अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के साथ खेल भावना और आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करेंगे।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना तथा बच्चों एवं युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।

गोल बाजार स्थित बाफना लाइफस्टाइल की छत पर मिला 21 वर्षीय युवती का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका



निष्पक्ष जांच, संस्थान को सील करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ जगदलपुर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के व्यस्त गोल बाजार स्थित बाफना लाइफस्टाइल की सबसे ऊपरी छत पर सोमवार सुबह 21 वर्षीय युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवती की मौत को संदिग्ध बताते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और संस्थान के सामने जमकर हंगामा किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच, संस्थान को सील करने और दोषियों के खिलाफकड़ी कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के अनुसार, बाफना लाइफस्टाइल में कपड़ों और ज्वेलरी का कारोबार संचालित होता है। मृतका करीब एक सप्ताह पहले ही यहां काम पर लगी थी। सोमवार सुबह उसकी मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि बाफना लाइफस्टाइल की छत पर एक युवती ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना से आक्रोशित परिजनों ने शोरूम के सामने प्रदर्शन करते हुए मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि मामले की हर पहलू से जांच की जाए और जांच पूरी होने तक संस्थान को सील रखा जाए। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। युवती की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

धान खरीदी को लेकर प्रशासन अलर्ट, 15 नवंबर से शुरू होगा उपार्जन

28 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित, केंद्रों पर नोडल अधिकारी करेंगे नियमित निरीक्षण

अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत देने और ग्रामीण विकास कार्यों को दो माह में पूरा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

ओमप्रकाश रजक/ जनता के गोठ

जगदलपुर, / कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर आम जनता को शासकीय सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अतिवृष्टि से प्रभावित मकानों और फसलों का तहसीलदारों को मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों



का ग्राम सभाओं में वाचन कराने को कहा, ताकि फसल और रकबे से संबंधित आपत्तियों का निराकरण हो सके। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित राजस्व प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रत्येक विकासखंड में बिहान कैंटीन, ग्रामीण लाइब्रेरी, खेल मैदान और आदर्श गोठान जैसे कार्यों को दो माह के भीतर मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में पूरा करने को कहा गया। वहीं सिकलसेल जांच, चिरायु योजना के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने तथा आयुष्मान कार्ड पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अंदरूनी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों के निर्माण और नए विद्युत सब-स्टेशनों के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने पर भी जोर दिया गया।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी

बैठक में आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी। इस वर्ष लगभग 28 लाख क्विंटल धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो नियमित रूप से केंद्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे। केंद्रों में चबूतरों का निर्माण, पर्याप्त बारदाना, फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरे, तिरपाल और भूसे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए खरीदी केंद्रों से धान का उठाव 15 जनवरी के बाद शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए राजस्व एवं खाद्य विभाग को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, डीआर डाहिरे, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बलौदाबाजार में धूमधाम से मना 26वां राज्योत्सवः सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोले– 'विष्णुदेव सरकार में लिखी जा रही विकास की नई गाथा'

'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में भव्य आयोजन; विकास व संस्कृति का दिखा अनूठा संगम

पीएम आवास की चाबियां, भूमि अधिकार पत्र और सुरक्षा योजनाओं के चेक वितरित; बाढ़ राहत दल व देहदान करने वालों के परिजन सम्मानित

रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ फोरलेन से जल्द सुगम होगा सफर; गांव-गांव तक पहुंची बुनियादी सुविधाएं: सांसद





तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह सोमवार को पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय हाई स्कूल मैदान में उल्लास व गरिमा के साथ संपन्न हुआ।

देश में सबसे तेज गति से विकास कर रहा छत्तीसगढ़: बृजमोहन अग्रवाल

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं दीं।

वीरों और संतों की भूमि है बलौदाबाजार: गौरीशंकर अग्रवाल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से प्रदेश और जिले में चहुंमुखी विकास धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

हितग्राहियों को मिली योजनाओं की सौगात, सेवाभावी नागरिक सम्मानित

समारोह के मंच से शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया: गायिका पायल साहू की सुरीली आवाज और लोकनृत्यों ने बांधा समां राज्योत्सव की सांस्कृतिक संध्या में लोकसंस्कृति की सतरंगी छटा बिखरी।

प्राक लोकमंथन में छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य और संगीत का हुआ प्रस्तुतीकरण

कोरबा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास के द्वारा लोक साहित्य पर केंद्रित प्राक लोकमंथन 2026 हम भारत के लोग कार्यक्रम विवेकानंद सेवा सदन, कोरबा में किया गया। छत्तीसगढ़ी लोकगीत और साहित्य पर यहां प्रस्तुति हुई। राजस्थान के जयपुर में 4 से 6 दिसंबर को होने वाले मुख्य समारोह मंथन में देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार शामिल होंगे। मुख्य वक्ता योगेश्वर साहू, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि लोक को आधार मानते हुए यह आयोजन यहां पर हुआ है। व्यापक दृष्टिकोण के साथ संगीत, साहित्य और लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की कोशिश हुई है। उन्होंने विवेकानंद के विदेश से जुड़े प्रसंग के माध्यम से अपने विचार को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लोक जीवन को प्रभावित करने के लिए साहित्य और संगीत की अपनी विशेष भूमिका होती है और इसलिए लंबे समय के बाद भी इनका हर जगह अपना विशेष महत्व बना हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर किए जा रहे इन प्रयासों को मुख्य वक्ता ने सराहा। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार गेंदलाल शुक्ल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि से अपने विचार रखे और स्पष्ट किया की लोकगीत और स्वरचित गीतों के बीच बुनियादी अंतर होता है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों की पहचान उसकी विषय वस्तु और विभिन्न आयाम से होती रही है। इस प्रकार के गीत बहुत लंबे समय से प्रचलन में है और जो अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। जबकि स्वरचित गीतों की अवधि कुछ समय पहले की है। उन्होंने कुछ वर्ष पहले तैयार किए गए राज्य गीत को लेकर भी अपना मनतव्य रखा। शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्राचार्य भूपेंद्र कुमार पटेल ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपनी बात रखी और इस लोक साहित्य और संगीत से संबंधित इस खास आयोजन की सराहना की। आयोजन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के द्वारा लोक संगीत की शानदार प्रस्तुति की गई। स्थानीय साहित्यकारों ने रचना पढ़ी। कार्यक्रम के प्रारंभ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मार्गदर्शक डॉक्टर देवदास साकेत ने अतिथियों का शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन अजय दास वैष्णव, संयोजक ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तिवारी, प्राचार्य मृगेश यादव, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पापिया चतुर्वेदी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफीसर जितेंद्र साहू, कार्यक्रम की योजना से जुड़े कैलाश नाहक।

पटवारी हड़ताल से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, बलियार तालाब निर्माण अधूरा; मजदूरों का भुगतान भी लंबित

बस्तर के युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए ङ्क जानकीराम सेठिया

जगदलपुर/बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के कांग्रेस नेता जानकीराम सेठिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पटवारी संघ की हड़ताल, बलियार तालाब के अधूरे निर्माण कार्य और बस्तर के युवाओं के पलायन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है। सेठिया ने कहा कि पटवारी संघ की हड़ताल के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व से जुड़े छोटे-छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। कई लोग सुबह से शाम तक पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की नीतियों का खामियाजा बताते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की।



उन्होंने बकावंड स्थित बलियार तालाब के सीसी लाइन जीर्णोद्धार कार्य पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, वर्ष 2023 में पूरा होने वाला यह निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम लंबित है तथा कार्य में लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है।

सेठिया ने कहा कि बस्तर संभाग में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, बलियार तालाब का निर्माण पूरा कराने तथा मजदूरों का बकाया भुगतान तत्काल कराने की मांग की।

'महतारी वन्दन योजना' बनी 70 लाख महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन और सम्मान का आधार : सांसद लक्ष्मी वर्मा



तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

विष्णुदेव साय सरकार की पारदर्शी नीतियों से धरातल पर दिखा सीधा बदलाव; मोदी की गारंटी हुई पूरी डीबीटी प्रणाली से सीधे बैंक खातों में पहुंच रही राशि, बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त प्रतिमाह मिल रही वित्तीय सहायता से संवर रहा घरेलू बजट, महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'महतारी वन्दन योजना' को छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तीकरण के इतिहास का ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। कागजों से निकलकर धरातल पर उतरी योजना सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में महिला कल्याण की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित थीं... डीबीटी से सीधे बैंक खातों में 1,000 रुपये प्रतिमाह योजना की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए सांसद ने बताया कि इसके तहत प्रदेश की पात्र विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये... तय तारीख पर किस्त मिलने से घरेलू बजट को मिली मजबूती श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर किस्त जारी होने से परिवारों के घरेलू बजट को स्थिरता मिली है।

ओबीसी महासभा ने बस्तर में युवा संगठन को दी नई जिम्मेदारी, मनोज कुमार ठाकुर बने जिला अध्यक्ष

देवनाथ ठाकुर को जिला उपाध्यक्ष और सदासिंह ठाकुर को बस्तर संभाग सचिव की जिम्मेदारी

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ।* ओबीसी महासभा ने संगठनात्मक मजबूती और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में बस्तर जिले में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। संगठन की ओर से मनोज कुमार ठाकुर को ओबीसी महासभा युवा प्रकोष्ठ बस्तर जिला अध्यक्ष, देवनाथ ठाकुर को जिला उपाध्यक्ष तथा सदासिंह ठाकुर को बस्तर संभाग सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन नियुक्तियों के माध्यम से संगठन ने बस्तर संभाग में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने की पहल की है। ओबीसी महासभा का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर जोड़ना, सामाजिक एकता एवं आपसी समन्वय को बढ़ावा देना तथा समाज से जुड़े मुद्दों को संगठित रूप से उठाना है।







नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, युवाओं को जोड़ने और समाज के लोगों के बीच संवाद एवं जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। संगठनात्मक विस्तार के साथ ही सामाजिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व और समाज के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।

ओबीसी महासभा में युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी मिलने से बस्तर जिले में संगठन की गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभचिंतकों एवं समाज के लोगों ने बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं।

बेमेतरा में धूमधाम से मना 26वां राज्योत्सवः सांसद विजय बघेल बोले– 'मोदी और साय के नेतृत्व में समृद्ध व आत्मनिर्भर बन रहा छत्तीसगढ़'

बेसिक स्कूल मैदान में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन, सांस्कृतिक छटा और विकास प्रदर्शनियों ने मोहा मन

शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से बदल रही जिले की तस्वीर; मेधावी छात्र और उत्कृष्ट विभाग हुए सम्मानित





तरुण बन्छोर- जनता के गोठ(रायपुर)

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह गरिमामय व उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

जनहितैषी योजनाओं से हर वर्ग का सशक्तिकरणः सांसद विजय बघेल

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री बघेल ने कहा कि राज्योत्सव केवल स्थापना का उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा... बुनियादी सुविधाओं और सिंचाई के विस्तार को प्राथमिकताः विधायक दीपेश साहू

समारोह में विधायक दीपेश साहू ने कहा कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। समृद्ध राज्य के निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरीः विधायक ईश्वर साहू

विधायक ईश्वर साहू ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश को सशक्त, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। सुशासन, विकास और जल संरक्षण प्रशासन का ध्येयः कलेक्टर

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले में शांति, सुशासन, अधोसंरचना विकास और जल संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी के साथ उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, प्रतिभागी हुए पुरस्कृत

समारोह के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी।

पारिवारिक रंजिश और शक में जेठ ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा/जनता के गोठ। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में छोटे भाई की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जेठ को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पारिवारिक रंजिश और मृतिका के चरित्र को लेकर संदेह के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले महिला का गला दबाया और फिर टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को बीरसिंग निषाद निवासी ग्राम मोहगांव ने अपनी पत्नी हेमलता निषाद की हत्या की सूचना पुलिस को दी। उसने अपने बड़े भाई देवसिंग निषाद पर हत्या का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा ने अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। एफएसएल टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके से खून के निशान, टूटी चूड़ियां और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात के बाद आरोपी देवसिंग फरार होकर गांव के पास नहर किनारे छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि हेमलता के किसी युवक से बातचीत करने को लेकर उसे संदेह था। इसी बात पर विवाद और गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टंगिया और खून से सने कपड़े जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूर्व में भी मृतिका से छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।



नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का एक परिचयत्मक बैठक 4 को

दुर्ग जिला एनजीओ प्रकोष्ठ का गठन,

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह एवं महामंत्री नवीन मार्कंडेय के मार्गदर्शन एवं प्रदेश संयोजक प्रदेश एनजीओ प्रकोष्ठ के दिनेश सिंह एवं संभाग दुर्गा के प्रभारी राकेश साहू की दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक की सहमति से दुर्ग जिला एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज ठाकरे द्वारा आज अपने संगठन का गठन किया। वह इस प्रकार

सहसंयोजक-6, मीडिया प्रभारी-2 आईटी सेल प्रभारी 2

सोशल मीडिया प्रभारी 2

कार्यालय सह प्रभारी-1

कोषाध्यक्ष एक-1

मन की बात प्रभारी-2

एवं58 बड़ी कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की। जो इस प्रकार जिला सहसंयोजक मोगरा देशमुख, श्रीमती गीता सोनी श्रीमती ललिता सिंह श्रीमती निका पांडेय, श्रीमती रूपेश्वरी साहू, श्री निरंजन जैन, जिला कोषाध्यक्ष सतीश यादव, जिला कार्यालय से प्रभारी किशोर कन्नौज, मीडिया प्रभारी सतीश बंजारे सोशल मीडिया प्रभारी कृष्णमूर्ति आर्य, हिमांशु साहू आर्य, आईटी सेल प्रभारी धर्मराज रावत सह प्रभारी भास्कर भट्टाचार्य मां की बात प्रभारी इंद्रपाल कौर सब प्रभारी श्रीमती मीरा वर्मा जिला कार्य कुर्मी सदस्य श्रीमती शीला वाघमारे श्रीमती रुक्मणी चतुर्वेदी श्रीमती चंद्र कल्याण मिश्रा श्री देवाशीष घोष कमलेश मंडलोई विनोद राय श्री पवन वैष्णव श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव श्रीमती रुक्मणी मजूमदार श्री आरती शर्मा श्रीमती लता मानिकपुरी श्रीमती विद्या प्रकाश कुंभकार अरुण सावरकर, पार्वती, बालू राम वर्मा अभिषेक टंडन प्रशांतक्षीरसागर, श्री रवि सोनी, श्री संजय वासु



भाजपा कार्यालय दुर्ग में की किस अवसर पर जिला संयोजक मनोज ठाकरे ने बताया

भारत के सभी 28 राज्यों एवं आठ केंद्र शासित प्रदेशों में गो प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी एवं लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिला की कार्यकारिणी भी जिले के गांव गांव तक जाकर शहर के जनमानस तक योजनाओं की जानकारी एवं उन्हें प्रमुख रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह एवं समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण एवं ऋण दिलाने का एवं साथ में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करेंगे।

दिनांक 4 नवंबर को दिन बुधवार को भाजपा कार्यालय दुर्ग में जिला एनजीओ प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का एक परिचयत्मक बैठक भाजपा कार्यालय जिला दुर्ग में दोपहर 3:30 बजे दिन बुधवार को रखी गई है । इस बैठक में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के अलावा प्रथम बार प्रदेश के प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह एवं प्रमुख संभाग के प्रभारी राकेश साहू प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे इस बैठक में सभी गाड़ी एवं कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति के लिए जिला संयोजक मनोज ठाकरे द्वारा की गई है ।

18 गांव के दर्जनों ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग





प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कवर्धा/जनता के गोठ। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में कथित धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। मंगलवार को जिले की 18 से अधिक गांव के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधि आज एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कथित धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में लागू धर्मांतरण कानून के तहत मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसों का लालच देकर तथा बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर लोगों की धार्मिक आस्था बदलने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने इस कथित गतिविधि में कुछ स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि धर्म परिवर्तन कर चुके कुछ कर्मचारी भी इस गतिविधि में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रलोभन अथवा दबाव के जरिए अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कथित प्रलोभन और दबाव के जरिए कराए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ है। उनका मानना है कि ऐसी गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो वनांचल की पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब ज्ञापन सौंपे जाने के बाद ग्रामीणों की शिकायतों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।

संपादकीय

वोट चोरी का मुद्दा

कांग्रेस ने सहयोगी दलों के सहयोग से दिल्ली के रामलीला मैदान में तथाकथित वोट चोरी के बहाने भीड़ जुटा ली इस रैली में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर को लेकर वही सब कहा, जो पिछले लंबे समय तक कहते चले आ रहे हैं। इसमें संदेह है कि यह रैली विपक्ष के इस नैरेटिव को विश्वसनीयता प्रदान कर सकेगी कि एसआइआर के जरिये विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि वोट चोरी का शोर मचाकर जो माहौल बनाया जा रहा है, उसका वही हश्र हो, जो इस दुष्प्रचार का हुआ था कि ईवीएम के कारण विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को वोट चोरी का अपना अभियान तेज करने का जरिया कुछ दिन पहले की उस खबर से मिला, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि एसआइआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर स्पष्ट रूप से कहा कि एसआइआर पर सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से हुए। इसके बाद भी विपक्षी दल अपने इस हठ पर कायम हैं कि वोट चोरी हो रही है। वे इस तथ्य पर भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं कि जिन 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट हटाए गए हैं, वे उनके हैं जो अन्यत्र जा बसे हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा जिनके नाम दो-तीन जगह दर्ज थे। सच यह भी है कि 13 करोड़ लोगों का नाम हटाने का फैसला अंतिम नहीं है और वैध मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में अभी भी शामिल करा सकते हैं। विपक्ष इस सच से भी मुंह मोड़ रहा है कि एसआइआर की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में सुधार के कई सुझाव देने के साथ लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए अतिरिक्त सुविधा एवं समय प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। इस सबके बावजूद विपक्षी दल वोट चोरी का राग अलापने में लगे हुए हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआइआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विपक्षी नेता कथित वोट चोरी के खिलाफ कोई प्रमाण कोर्ट के समक्ष पेश करने के बजाय दिखावटी संसद बुलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग पारित करने जैसे स्वांग कर अपना ही उपहास ही उड़ा रहे हैं। एक विडंबना यह भी है कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे कई विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस बूथ लेवल अफसरों की ओर से होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल एजेंट के तौर पर नियुक्त करने को लेकर उदासीन है।

गरीबी से मुक्तिः भारत में उम्मीद का नया उजाला

- ललित गर्ग



किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विस्तार अथवा वैश्विक आर्थिक रैंकिंग से नहीं किया जा सकता। विकास की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, निर्धनता का दायरा सिमटे, सामान्य नागरिक के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का संचार हो, गरीबी का कलंक मिटे तथा आर्थिक अवसरों पर सबका समान अधिकार स्थापित हो। इस दृष्टि से भारत में गरीबी और निर्धनता के स्तर में आई उल्लेखनीय गिरावट एक ऐतिहासिक उपलब्धि और नए भारत के निर्माण का शुभ संकेत है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की इस प्रगति को वैश्विक स्तर पर गरीबी में आई सबसे तेज गिरावटों में से एक माना जाना इस उपलब्धि को और महत्वपूर्ण बनाता है। यह केवल आर्थिक आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है, एक शुभ एवं श्रेयस्कर भविष्य की आहट है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में अत्यधिक निर्धनता की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय निर्धनता सीमा के अंतर्गत आने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ है कि लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। वर्ष 2028 तक इस अनुपात के 12.1 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। ये आंकड़े भारत की आर्थिक और सामाजिक यात्रा में एक बड़े परिवर्तन के प्रमाण हैं। विशेष बात यह है कि भारत ने इतनी बड़ी आबादी, व्यापक सामाजिक विविधता और कोविड जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद निर्धनता कम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, यह मोदी सरकार की युगान्तरकारी जन-कल्याण योजनाओं एवं गरीबी उन्मूलन के संकल्पों का ही परिणाम है। इस परिवर्तन के पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि विकास को जनकल्याण से जोड़ने की नीति भी महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना और मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाओं ने निर्धन परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने का काम किया है। इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इन्होंने गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, भोजन और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़कर उसका समाधान करने का प्रयास किया है। किसी निर्धन परिवार को पक्का मकान मिलना केवल आवास की उपलब्धता नहीं, बल्कि उसे संपत्ति, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना है। घर में बिजली, शौचालय और नल से जल की सुविधा उपलब्ध होना उसके जीवन की गुणवत्ता में बुनियादी परिवर्तन लाता है। जनधन खातों और आधार जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिकों को वित्तीय एवं वैधानिक पहचान प्रदान की है। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य संकट के समय गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का आधार तैयार किया है। विश्व बैंक ने गरीबी में कमी के प्रमुख कारणों में उपभोग में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार, विशेषकर महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक कल्याणकारी हस्तांतरणों की भूमिका को रेखांकित किया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच रोजगार में लगभग 13.4 करोड़ लोगों की वृद्धि होना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक सक्रियता परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करती है। ग्रामीण भारत में निर्धनता की तेज गिरावट ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक अंतर को भी कम करने में योगदान दिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक गिनी सूचकांक है, जिसके माध्यम से आय अथवा उपभोग के वितरण में असमानता का आकलन किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक 23 तक पहुंचा है, जो अपेक्षाकृत कम असमानता का संकेत देता है। यह अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में भारत की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि यहां यह समझना आवश्यक है कि उपभोग आधारित गिनी सूचकांक समाज में संपत्ति, आय और अवसरों की समग्र असमानता का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए गरीबी में कमी को आर्थिक समानता की पूर्ण उपलब्धि मान लेना उचित नहीं होगा। यही वह बिंदु है, जहां भारत की विकास यात्रा का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। एक ओर करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी ओर समाज में संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। उच्च आय वर्ग और सामान्य मेहनतकश नागरिक के बीच जीवन की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसरों का अंतर अभी भी व्यापक है।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार महत्वपूर्ण, पर भीड़तंत्र खतरनाक

- रमाकांत शर्मा



आधुनिक राजनीतिक दर्शन में लोकतंत्र को केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि संवाद, विमर्श और असहमति के सह-अस्तित्व की सतत प्रक्रिया माना जाता है। परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनी वैधता और स्थायित्व तब प्राप्त करती हैं, जब नागरिकों को व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाने और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का पर्याप्त अवसर मिलता है। असहमति को लोकतंत्र का सुरक्षा-वाल्व माना जाता है। इसके वैधानिक रास्ते बंद होने पर राजनीतिक व्यवस्था में अव्यवस्था की आशंका बढ़ जाती है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण, सत्याग्रह-प्रेरित और कानून के दायरे में होने वाले जन आंदोलनों की जगह धीरे-धीरे आक्रामक, अनियंत्रित और व्यवस्था-विरोधी भीड़तंत्र लेता जा रहा है। जब असहमति सार्वजनिक जीवन को बाधित करने, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक तंत्र को बंधक बनाने का रूप लेती है, तब लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलने लगता है। कानूनों में संशोधन, विकास योजनाओं और संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों ने वैध जनविरोध और अराजक भीड़तंत्र के बीच अंतर निर्धारित करने का बुनियादी प्रश्न खड़ा कर दिया है।

दक्षिण एशिया से पश्चिमी यूरोप तक की घटनाएं दर्शाती हैं कि जब जनांदोलन संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलने लगता है। वर्ष 2022 में श्रीलंका के 'अरगलाया' आंदोलन और नेपाल में लगातार हुई नाकेबंदियों ने संस्थागत स्थिरता को कमजोर किया। वहीं अगस्त 2024 में बांग्लादेश का आरक्षण-विरोधी आंदोलन हिंसक सत्ता-परिवर्तन में बदल गया, जिसके बाद संसद, न्यायपालिका और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं गंभीर संकट में आ गईं। पश्चिमी लोकतंत्र भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन और अल्बानिया में लोग सरकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

फ्रांस में महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन कुछ स्थानों पर आगजनी, लूटपाट और पुलिस के साथ झड़पों में बदल गए। इटली और बेल्जियम में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इन देशों में वैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय सड़क पर अराजकता के जरिये निर्णय हासिल करने की कोशिश चिंताजनक है। भारत के लिए भी यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ घरेलू तत्व इस अराजकता से कुप्रेरणा लेकर 'ढाका की तर्ज पर दिल्ली में 'रिजीम चेंज' का आह्वान कर रहे हैं।

गहरे मतभेदों और लंबे आंदोलनों के बावजूद भारत तीन प्रमुख आधारों पर अपने पड़ोसी देशों (श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल) की तरह संस्थागत पतन या तख्तापलट से बचा रहा है। पहला, पड़ोसी देशों से अलग भारतीय सेना पूरी तरह गैर-राजनीतिक रही है और उसने हमेशा निर्वाचित नागरिक सरकार तथा संविधान के अधीन अपनी भूमिका निभाई है। दूसरा, संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्यों में होने वाले नियमित चुनाव 'सुरक्षा वाल्व' का काम करते हैं। इनके माध्यम से जनता का असंतोष सड़कों पर लंबे समय तक बने रहने के बजाय मतपेटियों के जरिये अभिव्यक्त होता है। तीसरा, सक्रिय न्यायपालिका ने कार्यपालिका और प्रदर्शनकारियों के बीच संवैधानिक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।

असहनीय हो चुकी है न्याय में देरी

संजय गुप्त

इस कथन से शायद ही कोई अपरिचित हो कि 'न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है, लेकिन बार-बार की देरी तो अन्याय है।' महान संवैधानिक विशेषज्ञ एवं न्यायविद् नानी पालकीवाला का यह कथन भी खूब प्रचलित है कि भारत में न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी खामी देरी है और मैं दुनिया के किसी भी ऐसे देश से अवगत नहीं जहां मुकदमे इतने लंबे समय तक चलते हों, जितने भारत में। उनका यह भी कहना था, भारत में कानून बहुत ज्यादा हैं और न्याय बहुत कम। ये सभी चर्चित कथन भारतीय न्यायपालिका के समक्ष खड़ी चुनौतियों की गंभीरता को ही बयान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी और नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलएटी की प्रशासनिक स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी करना कि इन संस्थाओं को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 'पूरी तरह हाईजैक' कर लिया है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल विशेष ट्रिब्यूनल या न्याय मंच बना देने भर से त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। इन संस्थाओं में भारी रिक्तियों, बुनियादी ढांचे के अभाव और प्रशासनिक नियंत्रण में ढिलाई के कारण मुकदमों का निपटारा हफ्तों या महीनों में होने के बजाय सालों-साल खिंच जाता है, जिससे व्यावसायिक विवादों और आम नागरिकों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति होती है। यह विडंबना ही है कि जिन विशेष संस्थाओं का गठन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया था, वे स्वयं प्रशासनिक और व्यवस्थागत जकड़न का शिकार हैं। निचली अदालतों, अपीलीय ट्रिब्यूनलों और न्याय के अन्य मंचों पर मुकदमों के निस्तारण में लंबी देरी और कई बार आने वाले अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण फैसलों का एक सबसे बड़ा कारण जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। अक्सर निचली अदालतों द्वारा पारित सतही या कानूनी रूप से कमजोर निर्णयों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उन पर कड़ी टिप्पणियां भी की जाती हैं, परंतु यह बात कभी सार्वजनिक नहीं होती कि ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ अंततः क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? इसके विपरीत इन न्यायाधीशों की पदोन्नति का आधार और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है, जिससे आम जनता और विशेष रूप से वादियों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। इस दोहरी चुनौती से पार पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि व्यवस्था की कमजोरी केवल प्रशासनिक या बुनियादी ढांचे के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन की कमी भी है। एक तरफ जहां कार्यपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायिक संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ देकर उनकी गति को बाधित करने वाले कारणों का निवारण करे, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका के भीतर भी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए बिना अनावश्यक विलंब के त्वरित निर्णय दें। केवल बुनियादी ढांचे की कमी को ही देरी का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि न्यायाधीशों के पास अपनी कार्यशैली और समय-प्रबंधन में सुधार करके स्थिति को काफी हद तक बेहतर बनाने की शक्ति होती है। इसका उन्हें उपयोग करना ही चाहिए।

नकली संसद में असली मुद्दे पर महाभियोग

- राकेश अचल



भारत के लोकतंत्र में एक नया दृश्य सामने आया है। देश की असली संसद से बाहर एक नकली संसद बैठी। वहां लोकसभा की तरह आसन था, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं, विपक्ष के नेता थे, प्रस्ताव था, आरोप थे और मतदान भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि यह संसद संविधान से मान्यता प्राप्त संसद नहीं थी। लेकिन इस नकली संसद में जो मुद्दा उठाया गया, वह नकली नहीं था। मुद्दा था देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही का। मुद्दा था मतदाता सूचियों का, एसआईआर का, वोट के अधिकार का और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का।

31 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन ने सार्वजनिक महाभियोग की प्रतीकात्मक कार्यवाही की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अध्यक्षता की। खरगे ने प्रस्ताव रखा और राहुल गांधी समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने अपनी बात थथंथथथं लगभग तीन घंटे की कार्यवाही के बाद ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर विपक्ष को नकली संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह केवल राहुल गांधी की राजनीतिक जिद थी? क्या यह विपक्ष की अपनी भड़ास निकालने का मंच था? या फिर असली संसद में लगातार अनसुने रह रहे सवालों को जनता के बीच ले जाने की एक राजनीतिक कोशिश?

सबसे पहले उन छह आरोपों को समझिए, जिनके आधार पर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग चलाया।पहला आरोप—चुनावों को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूचियों में कथित तौर पर हेरफेर।दूसरा आरोप—एसआईआर के दौरान 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप।तीसरा आरोप—मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में संसद की मंजूरी के बिना बदलाव किए जाने का आरोप।

चौथा आरोप—ईआरओनेट और ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूचियों पर नियंत्रण केंद्रीकृत करने का आरोप।पांचवां आरोप—चुनाव आयोग के बाकी दो आयुक्तों को महत्वपूर्ण फैसलों से बाहर रखने का आरोप।और छठा आरोप—चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता से समझौता करके सत्ता पक्ष के हित में काम करने का आरोप।

इन आरोपों की सच्चाई का अंतिम फैसला किसी राजनीतिक मंच पर नहीं हो सकता। इसके लिए दस्तावेज, जवाब, जांच और संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन इन आरोपों को उठाने का विपक्ष का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अब जरा इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि देखिए।विपक्ष ने पहले संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस दिए थे। विपक्ष का दावा है कि 193 सांसदों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। लेकिन दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने उन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया।विपक्ष का कहना है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया के रास्ते ही बंद हो गए, तब जनता की अदालत में जाने के अलावा और क्या रास्ता बचा था?

यहां एक संवैधानिक तथ्य भी समझना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना किसी सामान्य सरकारी अधिकारी को हटाने जैसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी है। इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। इसलिए खरगे के आवास पर हुआ मतदान वास्तविक महाभियोग नहीं था। उससे ज्ञानेश कुमार का पद नहीं जा सकता।लेकिन क्या किसी राजनीतिक प्रस्ताव का कानूनी रूप से बाध्यकारी न होना उसे राजनीतिक रूप से महत्वहीन बना देता है?

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस आयोजन पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अनोखे नेता राहुल गांधी की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए मॉक संसद का भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने विश्व बैंक की गरीबी संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।

अब गरीबी कम हुई या नहीं, यह अपने आप में बहस का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का गरीबी के आंकड़ों से क्या जवाब दिया जा सकता है? अगर सरकार के पास चुनाव आयोग की निष्पक्षता और एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में जवाब हैं तो उन्हें सामने रखना चाहिए।

विपक्ष के आयोजन को नाटक कहना आसान है। लेकिन यह भी पूछना चाहिए कि विपक्ष को इस तरह का आयोजन करने की नौबत क्यों आई?क्या असली संसद में चुनाव आयोग की जवाबदेही पर पर्याप्त बहस हुई? क्या मतदाता सूची में नाम कटने की शिकायतों पर देश को संतोषजनक जवाब मिला? क्या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों का संसदीय परीक्षण हुआ?और अगर विपक्ष संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो क्या उसे सड़क, जनसभा और सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए?

वैसे मॉक संसद का विचार भारत में नया नहीं है। युवा संसद और प्रतीकात्मक संसदीय कार्यवाहियां पहले भी होती रही हैं। लेकिन किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का इस तरह सार्वजनिक महाभियोग आयोजित करना एक असाधारण राजनीतिक प्रयोग है।इसका कानूनी असर नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक असर हो सकता है।

पहला असर यह कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची का सवाल अब केवल संसद के भीतर का सवाल नहीं रहा। इसे जनता के बीच ले जाने की कोशिश हुई है।दूसरा असर यह कि विपक्षी दलों को एक साझा मंच मिला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के नेताओं की मौजूदगी इस एकजुटता का संकेत है। तीसरा असर यह कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से कटने की शिकायतें हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मंच मिला। नागरिक समाज और छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी ने इस आयोजन को केवल नेताओं की सभा बने रहने से आगे बढ़ाया।और चौथा असर यह कि सत्ता पक्ष को भी अब इस सवाल का राजनीतिक जवाब देना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है। यानी बहस का सवाल खुद राजनीतिक बहस बन गया है। लेकिन विपक्ष के सामने भी चुनौती कम नहीं है। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उसे आंकड़ों, दस्तावेजों और प्रभावित मतदाताओं के प्रमाणों के साथ अपनी बात साबित करनी होगी।

आज का राशिफल

मेष राशि :- कुटुम्ब और धन की चिन्ता बनी रहे, परिश्रम से सोचे कार्य अवश्य ही बनेंगे, ध्यान दें।

वृष राशि :- अधिकारियों के समर्थन से सफलता, कार्य कुशलता से संतोष होवे, बिगड़े कार्य बनेंगे।

मिथुन राशि :- चिन्ताएं कम हो, सफलता के साधन जुटाए तथा शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे।

कर्क राशि :- बड़े-बड़े लोगों से मेल मिलाप होवे तथा सुख समृद्धि के साधन अवश्य बनेंगे।

सिंह राशि :- स्त्रीवर्ग से हर्ष उल्लास होवे, भोग कार्य की प्राप्ति होगी, कार्य गति उत्तम बनें।

कन्या राशि :- प्रतिष्ठा बाल बाल बचें, संघर्ष से अधिकार प्राप्त करें, भाग्य का साथ दें।

तुला राशि :- धन का व्यय संभव है, तनाव पूर्ण वार्ता से बचिएगा, कार्य का ध्यान अवश्य रखें।

वृश्चिक राशि :- प्रत्येक कार्य में बाधाएं, क्लेश युक्त रखे, स्थिति साम्थर्य के योग अवश्य बनें।

धनु राशि :- भावनाएं विक्षुब्ध रखे, दैनिक कार्यगति मंद रहे, परिश्रम से कार्य अवश्य बनेंगे।

मकर राशि :- तनाव क्लेश व अशांति, धन का व्यय, मानसिक खिन्नता, अवश्य बनेगी।

कुंभ राशि :- कार्य कुशलता से संतोष, व्यवसायिक समृद्धि के साधन।

मीन राशि :- कुटुम्ब के कार्यों में समय बीतें तथा हर्षप्रद समाचार प्राप्त हो।

ट्रंप प्रशासन को प्रभावित करने वाले चुनाव

अमेरिका के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मध्यावधि चुनाव हुआ हो, जिस पर दुनिया ने इतना ध्यान दिया हो। इसकी वजह कोई और नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनकी पलटू और अटपटी नीतियों ने उनके ही देश द्वारा स्थापित विश्व व्यवस्था में ऐसी उथल-पुथल मचाई है कि हर कोई उनसे निजात पाने की राह देख रहा है। हालांकि इस चुनाव में उनका भाग्य पूरी तरह दांव पर नहीं है। उनका आधा कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की समूची प्रतिनिधि सभा और सीनेट की एक तिहाई से अधिक सीटों का फैसला इन्हीं चुनावों में होना है। यह चुनाव प्रतिनिधि सभा के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद हो रहा है, जिससे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को लगभग नौ सीटों पर लाभ होने की आशा है। फिर भी जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार उनकी पार्टी का प्रतिनिधि सभा में तो हारना तय है ही, सीनेट भी हाथ से जा सकती है। राष्ट्रपतियों की पार्टी ने पिछले 20 मध्यावधि चुनावों में से 18 में प्रतिनिधि सभा की सीटें गंवाई हैं। इस समय ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास प्रतिनिधि सभा में मात्र दो सीटों का बहुमत है और सीनेट में तीन सीटों का। इसलिए उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के लिए ऐसे प्रचार किया है मानो वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हों। मतदाताओं से अपील की है कि वे उन्हें ही उम्मीदवार मानकर वोट दें। यही नहीं, उन्होंने भारत के चुनावों की तरह वोटरों को लुभाने के लिए पांच हजार डालर की रेवड़ी बांटने का वादा भी किया है। फिर भी एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार उनके काम से संतुष्टों का दायरा घटकर 31 प्रतिशत पर आ गया है और इतिहास बताता है कि यह आंकड़ा 50 से नीचे गिर जाने पर राष्ट्रपति की पार्टी को प्रतिनिधि सभा में औसतन 37 सीटों का नुकसान होता है। 2018 के मध्यावधि चुनाव में ट्रंप से संतुष्ट रहने वालों का प्रतिशत 41 पर आ जाने से रिपब्लिकन पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ था। विश्लेषकों का अनुमान है कि रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा की कम से कम 15 सीटों का नुकसान तो होना तय है और सीनेट की भी तीन-चार सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों में विपक्ष का बहुमत होने पर राष्ट्रपति के लिए सरकार चलाना कठिन हो जाता है। प्रतिनिधि सभा की सभी संसदीय और स्थायी समितियां विपक्ष के हाथों में चली जाती हैं जो हर विभाग के बजट, खर्च और कर्ज की सीमा निर्धारित करती हैं और विदेशी मामलों की नीतियां बनाती हैं। ये समितियां ट्रंप और उनके मंत्रियों पर जांच बिठा सकती हैं, उन्हें तलब कर सकती हैं और महाभियोग भी चला सकती हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के लिए तो सीनेट में दो तिहाई बहुमत चाहिए। इसीलिए एंड्रयू जांसन, बिल क्लिंटन और ट्रंप पर महाभियोग चलाने के बावजूद आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका है। इस बीच यह भी सुनने में आया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग की तैयारी कर रखी है। ट्रंप पर महाभियोग तो शायद ही चलाया जाए, लेकिन उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों पर पद का अनुचित लाभ उठाने की और भ्रष्टाचार की जांच बिठाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी ने पाकिस्तानी सरकार के साथ उस समय सौदा किया था, जब अमेरिका की क्रिप्टो नीति बन रही थी।

महिला से प्रेम संबंध , फिर शादी करने का बनाया भरोसा, झांसा देकर बनाए संबंध

फिर मुकरा युवक ; दुर्ग कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग - दुर्ग की अदालत ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शादी का भरोसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अवध किशोर की अदालत ने भिलाई निवासी योगेश कुमार साहू (33) को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

फैसला 2 नवंबर 2026 को सुनाया गया - अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आरोपी ने महिला को शादी का भरोसा देकर विश्वास में लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसका विवाह करने का इरादा नहीं था।

बुआ के घर आने - जाने के दौरान हुई थी पहचान -अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भिलाई निवासी योगेश कुमार साहू की बुआ महिला के घर किराए पर रहती थीं। इसी वजह से योगेश का वहां आना-जाना था और इसी दौरान उसकी महिला से पहचान हुई।

बाद में आरोपी ने अपने फुफेरे भाई के माध्यम से महिला का मोबाइल नंबर लिया। दोनों के बीच फोन और मैसेज पर बातचीत शुरू हो गई। महिला ने उसे अपने पहले तलाक के बारे में भी बताया था। इसके बावजूद योगेश ने महिला से प्यार और शादी करने की बात कही। वह अपने माता-पिता को लेकर शादी की चर्चा करने आने का भरोसा देता था। होली के अवसर पर वह महिला के घर भी गया और उसके परिवार के साथ त्योहार मनाया।

शादी की बात करने के बहाने घर पहुंचा आरोपी - मामले के अनुसार, 24 मार्च 2025 को योगेश ने महिला को फोन कर बताया कि वह शादी की बात करने उसके घर आ रहा है। दोपहर करीब 2:30 बजे वह वहां पहुंचा। उस समय महिला घर में अकेली थी। महिला ने अदालत में बताया कि उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हुए कहा था कि शादी के बाद ही ऐसा होगा। इसके बावजूद आरोपी ने विवाह का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद योगेश ने जल्द ही अपने परिवार को लेकर आने की बात कही और वहां से चला गया। महिला के बयान के मुताबिक, घटना के बाद उसी दिन शाम को आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कई बार फोन करने के बावजूद उससे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद महिला आरोपी के भिलाई स्थित घर पहुंची। वहां उसे



जानकारी मिली कि योगेश दूसरी युवती से शादी का रिश्ता तय करने के लिए खुरसुनी गांव गया है। महिला अपनी बहन के साथ खुरसुनी पहुंची और दूसरी युवती के परिवार को योगेश के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने आरोपी को बुलाकर पूछताछ की। इस दौरान योगेश ने महिला के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की। इसके बाद दूसरी युवती के परिवार ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि, आरोपी ने महिला से भी विवाह करने से इनकार कर दिया।

26 अप्रैल 2025 को दर्ज कराई शिकायत - आरोपी के शादी से इनकार करने के बाद महिला ने 26 अप्रैल 2025 को दुर्ग कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने योगेश कुमार साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रकरण अदालत में पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई

कोर्ट में संबंध स्वीकार, शादी के वादे से इनकार- सुनवाई के दौरान आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की, लेकिन शादी का झूठा भरोसा देने के आरोप से इनकार किया। उसका कहना था कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। बचाव पक्ष ने महिला की शिक्षा, दोनों के बीच पहले से बातचीत और घटना के दिन महिला के घर अकेले होने की जानकारी आरोपी को होने जैसे तथ्यों का उल्लेख किया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने महिला, उसकी मां और बहन के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने की मांग की।

मोबाइल बंद करना और दूसरी जगह रिश्ता तय करना बना अहम आधार - अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी और महिला के बीच पहले से पहचान और बातचीत थी, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। आरोपी ने अपने बयान में मोबाइल बंद करने और दूसरी जगह शादी का रिश्ता तय करने जाने की बात स्वीकार की थी। अदालत के मुताबिक, महिला का बयान प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडित रहा और उसके कई महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि आरोपी के बयान से भी हुई। इन परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी का शुरू से ही महिला से शादी करने का इरादा नहीं था। शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले को अदालत ने BNS की धारा 69 के तहत अपराध माना।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में वन्यजीव छायाकार हेमंत वर्मा सम्मानित: पक्षी संरक्षण और दुर्लभ 'मालाबार जायंट स्किरल' की ऐतिहासिक खोज को मिली पहचान

जनता के गोठ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर एवं पर्यावरण संरक्षक हेमंत वर्मा को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बर्डिंग (पक्षी संरक्षण), प्रकृति जागरूकता तथा देवपुर वन परिक्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ 'मालाबार जायंट स्किरल' (विशाल भारतीय गिलहरी) को कैमरे में कैद कर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए प्रदान किया गया है।





पेशे से साइबर सिक्योरिटी रिस्क ऑडिटर हेमंत वर्मा ने बर्ड ट्रेल्स और ग्रामीण संवाद के जरिए 200 से अधिक युवाओं को 'प्रकृति प्रहरी' के रूप में तैयार किया है। देवपुर समर कैंप के दौरान उनके द्वारा खोजी गई दुर्लभ मालाबार जायंट स्किरल ने न केवल बारनवापारा और देवपुर के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को प्रमाणित कर इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया, बल्कि शैक्षणिक जगत में भी बड़ा प्रभाव छोड़ाः

CG-PSC समसामयिकी में शामिलः उनकी इस ऐतिहासिक खोज को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) के करेंट अफेयर्स (समसामयिकी) में प्रमुखता से स्थान दिया गया। हाईकोर्ट DEO परीक्षा में सवालः छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CGVYA-PAM) द्वारा आयोजित उच्च न्यायालय डाटा एंट्री ऑपरेटर (High Court DEO) भर्ती परीक्षा में भी 'मालाबार जायंट स्किरल' से जुड़े प्रश्न पूछे गए। बलौदाबाजार जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से अनुशंसा के बाद जिला प्रशासन द्वारा मिले इस सम्मान पर जिले के पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया है।

शारदा संगीत विद्यालय का दीपावली मिलन समारोह 7 को

कमल खुंटे/जनता के गोठ

बिर्रा। गुरु घासीदास संगीत महाविद्यालय हसौद (सरगम संगीत समिति) के अध्यक्ष आर के सोनवानी के स्वप्न का 30वाँ संगीत समारोह पूर्ण गरिमा के साथ 25 अक्टूबर को पोंडी राछा (नवागढ़) में संपन्न होने के उपलक्ष्य में एवं प्रतिवर्ष दीपावली मिलन उत्सव की परंपरा को जारी रखते हुए संस्कार भारती जिला सक्ती के सहयोग से स्नेह सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर 2026 शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शारदा संगीत विद्यालय बिर्रा के आचार्य चाणक्य सभागार में मणीलाल कश्यप, एकादशिया साहू, दिनेश चंद्रा व रितेश रमण सिंह की मंगलमय उपस्थिति में किया जाएगा। जिसमें संगीत शिक्षकों का सम्मान, संगीतमय प्रस्तुतियां, संगीत के प्रचार-प्रसार पर विचार-विमर्श एवं संगीत विद्यालय के मीडिया प्रभारी पं जितेन्द्र तिवारी बिर्रा द्वारा संगीत उत्थान में प्रचार की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं इस वर्ष का थीम अपने संगीत परिवार की भूमिका रहेगा, जिसकी जानकारी शारदा संगीत विद्यालय बिर्रा के व्यवस्थापक मनोज कुमार तिवारी ने दी।

शिक्षक प्रतिभा अकादमी किया शिक्षिका भारती नीलम का सम्मान

जनता के गोठ/ओंकार साहू

बलौदाबाजार। 3नवंबर 2026। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित पंजीकृत संस्था शिक्षक प्रतिभा अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन, बिलासपुर में गरिमामय एवं भव्य वातावरण में विकासखंड के नवाचारी शिक्षक शिक्षिकाओं भारती वर्मा, नीलम वर्मा व मोहन वर्मा का सम्मान किया गया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लगभग 200 शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षाविदों ने सहभागिता की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाठक एवं सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी समाजसेवी तिलक डोरे की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को आधुनिक, व्यावहारिक एवं कौशल आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के समर्पण, प्रतिबद्धता एवं शैक्षिक नवाचारों से छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। समारोह का प्रमुख आकर्षण प्रदेश के लगभग 200 प्रतिभावान शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचार एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर शिक्षक प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि तोखन साहू के करकमलों से संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। वेबसाइट के माध्यम से संस्था की गतिविधियों, शैक्षिक पहलों एवं शिक्षक सशक्तीकरण से जुड़ी जानकारियों को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने की पहल की गई। विकासखंड के शिक्षक शिक्षकों के सम्मान पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव, एबीईओ ढालसिंह ठाकुर,राकेश सिंग, सी एस ध्रुव ने हर्ष व्यक्त किया ।

ग्राम पंचायत अमेरी एवं करगा सरपंच ने की पटवारी के खिलाफ गंभीर शिकायत

पटवारी को अन्यत्र नहीं हटाने पर दी आंदोलन की चेतावनी

पाटन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम एसडीएम ने पटवारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब पंचायत अमेरी एवं करगा सरपंच पहन 13 में पदस्थ पटवारी के खिलाफ कमिश्नर एवं कलेक्टर के समक्ष गंभीर शिकायतें की है। उन्होंने पटवारी को अन्यत्र नहीं हटाने पर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। उनके इस शिकायत के बाद एसडीएम पाटन ने पटवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। अमेरी सरपंच भूषण सेन एवं करगा सरपंच कमलेश ठाकुर द्वारा कमिश्नर एवं कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि पहन 13 में पदस्थ पटवारी आर.के. मिश्रा कभी भी कार्यालय में समय पर उपस्थिति नहीं होते हैं। वहीं कभी भी किसानों, सरपंच, पंचों एवं सचिव के फोन करने पर नहीं उठाते हैं। हर काम के लिए

एसडीएम ने आरोप को कार्यो के प्रति माना लापरवाही-एसडीएम ने पटवारी को जारी नोटिस में कहा है कि ग्राम पंचायत अमेरी के सरपंच द्वारा उनके विरुद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें की गई हैं। उक्त शिकायत में वर्णित आरोप अपने कार्यो के प्रति घोर लापरवाही, आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता से संबंधित हैं। जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है। पटवारी को उन्होंने निर्देशित किया है कि शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप के संबंध में अपना बिंदुवार लिखित स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, उनके हल्का क्षेत्र में लंबित नक्शा-बटांकन फौती नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व संबंधी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति तथा उनके लंबित रहने के कारणों का विवरण भी मांगे हैं। लोगों को परेशान किया जाता है। किसी भी कृषक का नक्शा आज तक दो वर्षों में नहीं काटा गया है। इसी प्रकार जाति, आय छात्रवृति में फार्म भरने समय भी छात्र-छात्राएं पटवारी कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। जिस कारण छात्र-छात्राओं को छात्रवृति नहीं मिल पाता। स्थिति यह है कि एक अति गरीब परिवार के राशन कार्ड पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया, इसके कारण दो तीन माह से उक्त परिवार को राशन नहीं मिल रहा है। वहीं पंचायत में अविवादित फौती नामांतरण, बटवारा प्रकरण पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, जिसके कारण समय सीमा भी समाप्त हो जाता है ऐसे में भटक रहे कृषक निरस्त करवाकर तहसील से अपना अविवादित फौती नामांतरण, बटवारा का कार्य पैसे देकर करवाते हैं। आम जनता के प्रति उनका व्यवहार सिर्फ पैसे के लिए रहता है, हर गरीब परिवार को घुमाते रहते हैं। उन्होंने पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की करने और स्थानांतरण कर इस समस्या से निजात दिलाने मांग।

गैस पाइपलाइन की खुदाई से टूटी नल-जल योजना, कई वार्डों में पेयजल संकट

पंचायत को बिना सूचना खोद दी सड़क, मरम्मत के नाम पर ठेकेदार के आश्वासन भी बेअसर

जनता के गोठ/ओंकार साहू

बलौदाबाजार जिला सिमगा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रिंगनी में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान नल-जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि गैस पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार ने ग्राम पंचायत को बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति दिए खुदाई कर दी, जिससे नल-जल योजना की मुख्य एवं वितरण पाइपलाइन टूट गई। इसके चलते कई वार्डों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है।

ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती मनीषा मेननजीत ने कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को शिकायत सौंपकर मामले में



तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत के अनुसार, ठेकेदार उमाशंकर शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे स्वयं ठीक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई।

सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत करवाकर पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए तथा बिना पंचायत को सूचना दिए खुदाई करने और सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के मामले में जिम्मेदार एजेंसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

अब देखना होगा कि ग्रामीणों की पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधायक पुरन्दर मिश्रा व गुजराती समाज का प्रतिनिधिमंडल, 'नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़' के लिए दी बधाई

पारंपरिक गमछा पहनाकर किया केंद्रीय गृह मंत्री का आत्मीय

विधायक पुरन्दर मिश्रा बोले- 'हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे' के संकल्प पर बढ़ रहा राज्य

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ रायपुर, 03 नवंबरः रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में गुजराती समाज के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान विधायक मिश्रा ने छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप गमछा पहनाकर गृह मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए निर्णायक अभियानों और 'नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

आंतरिक सुरक्षा और नक्सल उन्मूलन पर जताया आभार

भेंट के दौरान गुजराती समाज के पदाधिकारियों ने देशभर में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और विकास के क्षेत्र में अमित शाह के नेतृत्व की सराहना की। समाज के





प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण दशकों पुरानी नक्सल समस्या पर प्रभावी अंकुश लगा है। प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार नेटवर्क का विस्तार कर विकास की नई इबारत लिखी गई है, जिससे 31 मार्च 2026 तक तय किए गए नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार किया जा सका।

'हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे': विधायक पुरन्दर मिश्रा

मुलाकात के दौरान विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहाः छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हमारा संकल्प है– 'हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे'। यह महज एक नारा नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास और जनसेवा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है।÷ विधायक मिश्रा ने आगे कहा कि 'मोदी की गारंटी' केवल कागजी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुंच रही हैं। धारा 370 को समाप्त करने, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण से लेकर देश की सीमाओं व आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने जैसे ऐतिहासिक कदमों ने देश के सांस्कृतिक गौरव और संप्रभुता को मजबूती दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से 'विकसित भारत 2047' का विजन निश्चित रूप से साकार होगा।

प्रतिनिधिमंडल में ये प्रमुख लोग रहे मौजूद इस सौजन्य भेंट में गुजराती समाज के प्रमुख गणमान्य नागरिकों और पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप सेः विश्राम भाई छाभैया, वेलजी भाई रुडाणी, जयंती भाई छाभैया, लिलाधर भाई भगत, हरमुख भाई पटेल, देवजीभाई पटेल, जयंती पटेल, सूर्यकान्त भाई पदमाणी, दलपत भाई हलपाणी, चन्दू भाई नाकराणी, हिम्मत भाई छाभैया, तिलक भाई छाभैया, मुकेश पदमाणी, अम्बालाल धोनू, दिनेश भाई कनानी, ईश्वर भाई रुडाणी एवं प्रीतेश गाँधी शामिल थे। मुलाकात के अंत में प्रतिनिधिमंडल ने देश और राज्य के सुरक्षित व समृद्ध भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

कार्यालय जनपद पंचायत छुईखदान, जिला खैरागढ छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)
विज्ञप्ति

क्रमांक/3967/म.पा./ज.पं. /2026-27 छुईखदान, दिनांक 03.11.2026

जनपद पंचायत छुईखदान अन्तर्गत जलाशयो को दस वर्षीय पट्टे पर देने की सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत छुईखदान के अधिनस्थ निम्नांकित सिंचाई जलाशयों को दस वर्षीय पट्टे पर मछली पालन हेतु शासकीय नियमों एवं शर्तों के तहत दिया जाना है:-

क्रमांक	सिंचाई जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हेक्टे. में	प्रारंम्भिक पट्टा राशि
01	कोहकाझोरी जलाशय	15.69	21866 (जून 2026 में)
02	भेण्ड्रा जलाशय	71.80	105122 (जून 2026 में)
03	महाराटोला जलाशय	18.27	21500 (जून 2026 में)

पट्टा राशि में प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात दस प्रतिशत की वृद्धि होगी पट्टा राशि के साथ निर्धारित पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पट्टाधारक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधान अनुसार देय होगा।

आबंटन संबंधी जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत छुईखदान / मत्स्य निरिक्षक छुईखदान से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

आबंटन हेतु प्राथमिकता कम निम्नानुसार होगा:-

01. पंजीकृत मछुवारा सहकारी समिति 02. मछुआ समूह 03. मछुआ व्यक्ति 04. ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात मकान भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गए हों, ऐसे व्यक्तियों / परिवार या उनके समूह / समिति से संबंधित जलक्षेत्र पट्टे पर दिए जाने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। 05. उपर्युक्त चारों वर्ग यदि किसी ग्राम / क्षेत्र में न हों तो स्व सहायता समूह ।

टीप:-उसी क्षेत्र की पंजीकृत स्थानीय मछुआ सहकारी समिति से तात्पर्य तालाब/जलाशय से आठ किलोमिटर की परिधी मे पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति से है। यदि उस क्षेत्र की मछुआ सहकारी समिति/समूह से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो समीप के क्षेत्र की मछुआ सहकारी समिति / समूह को जलाशय का पट्टा आबंटित किया जावेगा।

आवेदन कार्यालय जनपद पंचायत छुईखदान में दिनांक 13-11-2026 तक जनपद पंचायत छुईखदान में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत छुईखदान

खबर-खास

जनपद पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा में गूंजेगा किसान मुआवजे का मुद्दा



अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। दुर्ग - किसान नेता एवं जनपद पंचायत दुर्ग के जनपद सदस्य ढालेश साहू ने बताया कि जनपद पंचायत दुर्ग में आयोजित होने वाली सामान्य सभा की बैठक में चक्रवात अर्नब से प्रभावित किसानों की फसल क्षति एवं मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से गूंजेगा। ढालेश साहू ने कहा कि चक्रवात अर्नब के चलते असमय हुई बारिश और तेज आंधी-तूफान से हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसान आज मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग और बीमा कंपनी की जवाबदेही तय करना जरूरी है।

सामान्य सभा में प्रमुख रूप से इन 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा जाएगा -1. चक्रवात अर्नब से प्रभावित गांवों में कितने किसानों का सर्वेक्षण हुआ? 2. कृषि विभाग ने फसल नुकसान का कितना आकलन किया है और प्रभावित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 3. सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से चयनित ऋण लेने वाले कितने किसानों के खातों से फसल बीमा प्रीमियम काटा गया है? 4. प्रभावित किसानों के बीमा क्लेम की वर्तमान स्थिति क्या है और बीमा कंपनी ने कितने दावों पर कार्रवाई की है? 5. पात्र किसानों को बीमा क्लेम एवं मुआवजे का भुगतान कब तक किया जाएगा? 6. सर्वेक्षण से वंचित रह गए किसानों के लिए दोबारा सर्वेक्षण की क्या व्यवस्था है? 7. जिन किसानों की फसल बीमा के दायरे में नहीं है, उन्हें शासन से किस प्रकार की राहत दी जाएगी? 8. प्रभावित गांवों की ग्रामवार और फसलवार क्षति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साहू ने मांग की है कि प्रभावित किसानों का निष्पक्ष सर्वेक्षण कराकर पात्र किसानों को शीघ्र बीमा क्लेम एवं मुआवजा दिया जाए और विभाग समय-सीमा में कार्रवाई करे।

ग्राम पहंदा में 28 दिसंबर से गूंजेगी शिव महिमा: सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन, पंडित रामानुज युवराज पाण्डेय करेंगे अमृतवर्षा

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ पाटन (दुर्ग): पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम पहंदा (अ) में देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आगामी 28 दिसंबर 2026 से 03 जनवरी 2027 तक सात दिवसीय भव्य श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन धार्मिक अनुष्ठान को लेकर गांव सहित समूचे अंचल में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है।



पूज्य पंडित रामानुज युवराज पाण्डेय कराएंगे शिव महिमा का रसपान- आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध संत एवं राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य आचार्य पंडित रामानुज युवराज पाण्डेय जी के श्रीमुख से श्रद्धालुओं को भगवान शिव के अलौकिक प्रसंगों, भक्ति, ज्ञान एवं आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने का सौभाग्य मिलेगा। कथा का नियमित वाचन प्रतिदिन दोपहर 1:00 बजे से 'प्रभु इच्छा तक' ग्राम पहंदा (अ) स्थित नया पानी टंकी गौठान के समीप होगा।

29 दिसंबर को सजेगा 'दई के दुलरवा' झांकी का मंच- इस धार्मिक महोत्सव को और अधिक भव्य व स्मरणीय बनाने के लिए 29 दिसंबर 2026 को विशेष सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। संध्या 7:00 बजे से छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध 'दई के दुलरवा' नवरत्न पटपर झांकी की मनमोहक प्रस्तुति होगी, जो इस पूरे आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेगी। झांकी के माध्यम से देवी-देवताओं के विविध रूपों और धार्मिक प्रसंगों का सजीव मंचन किया जाएगा।

तैयारियों में जुटी आयोजन समिति- कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था, पेयजल, छाया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने में शेखर निर्मलकर, सुरेन्द्र साहू, भारत वर्मा, राजेश्वर साहू, संदीप विश्वकर्मा, मुकेश, तुलेंद्र, रामकुमार, टूपेंद्र, संजय, कमलेश साहू एवं पूरण धीवर सहित गांव के वरिष्ठ नागरिक, युवा और मातृशक्ति सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। आयोजन समिति के सदस्य एवं भाजपा जिला महामंत्री (ओबीसी मोर्चा), दुर्ग सुरेन्द्र साहू ने पाटन क्षेत्र सहित आसपास के सभी धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं, माताओं-बहनों एवं युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार उपस्थित होकर शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागीदार बनें।

दुर्ग सांसद विजय बघेल के अथक प्रयास से भिलाई वासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर मिली बड़ी सौगात

रिटेंशन और थर्ड पार्टी दोनों को 6 रुपए प्रति वर्गफीट का लाभ

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। भिलाई / दुर्ग - छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर भिलाईवासियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भिलाई स्टील प्लांट की रिटेंशन स्कीम को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ी राहत दी गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय और सांसद विजय बघेल के प्रयासों से बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम के पूर्व नियमों को वापस ले लिया है। नए निर्णय के तहत अब रिटेंशन धारियों के साथ-साथ थर्ड पार्टी को भी 6 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से लाभ मिलेगा। शासन और प्रबंधन के स्तर पर सहमति बन चुकी है, जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होगा। लंबे समय से क्वार्टर आवासों को लेकर असमंजस झेल रहे हजारों परिवारों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। भिलाई वासियों ने और क्वार्टर आवासों में रहने वाले और जीवन यापन करने वाले परिवारों ने सांसद विजय बघेल के इस सफल प्रयास पर अपनी कृतज्ञता अर्पित कर उन्हें धन्यवाद दिया।



अटल जी के सपनों और मोदी के विजन से गढ़ा जा रहा 'विकसित छत्तीसगढ़': संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल

जनता के गोठ- रायपुर
रायपुर, 03 नवंबर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नवा रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय भव्य राज्योत्सव 2026 का रंगारंग समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंच नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, अस्मिता, स्वाभिमान और 26 वर्षों की विकास यात्रा का जीवंत प्रकटीकरण साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के अनुरूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अटल जी का ऐतिहासिक निर्णय और विकास का नया अध्याय संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य निर्माण के ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य का स्वरूप देना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की दूरगामी सोच का परिणाम था। उन्होंने जनभावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझते हुए अलग राज्य की सौगात दी, जिससे प्रदेशवासियों को अपनी नियति स्वयं गढ़ने का अवसर मिला। आज राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि भौतिक अधोसंरचना के विस्तार के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही विकसित छत्तीसगढ़ का मूल उद्देश्य है।



राज्योत्सव 2026: सांस्कृतिक वैभव और परंपरा का संगम- नवा रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव के स्वरूप पर चर्चा करते हुए संस्कृति मंत्री ने बताया कि इस बार का मंच परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बना। लोक एवं शास्त्रीय विधाएं: पंडवानी, पंथी, सुआ, करमा, राउत नाचा और बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नृत्यों के साथ-साथ कथक और ओडिसी की प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक विविधता की अनूठी छाप छोड़ी। शिल्पग्राम व विभागीय प्रदर्शनी: शिल्पग्राम में स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया, वहीं शासकीय विभागों की प्रदर्शनियों के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जीवंत झलक आम नागरिकों तक पहुंचाई गई। कलाकारों को मंच: आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं, लोककर्तकों और संगीतकारों को वृहद मंच प्रदान कर प्रोत्साहित करना रहा।

गृह मंत्री अमित शाह के आतिथ्य में संपन्न हुआ राज्य अलंकरण समारोह- राज्योत्सव 2026 का समापन देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समापन समारोह के दौरान राज्य अलंकरण से प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, खेल, समाजसेवा और जनसरोकार के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश की सृजनशीलता और सामूहिक परिश्रम का सार्वजनिक अभिनंदन है, जो भावी पीढ़ी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

आंधी आए या तूफान, छोटे देवड़ा में नहीं रुकेगी ट्यूशन क्लास

सरपंच संतोष कुमार कश्यप का संकल्प, हर परिस्थिति में जारी रहेंगी ट्यूशन कक्षाएं, शिक्षा की ज्योति जलाए रखने का संदेश

भुजबल बघेल 7
बकावंड जनता के गोठ।बकावंड विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा में शिक्षा के प्रति समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल पेश की जा रही है। यहां संचालित ट्यूशन कक्षाओं को नियमित रूप से जारी रखने का संकल्प लिया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने छात्र-छात्राओं को सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, आंधी आए या तूफान, बारिश हो या तेज धूप, ट्यूशन कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी बाधा शिक्षा की राह में रुकावट नहीं बन सकती। बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही हमारा लक्ष्य है।

सरपंच ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि रुकना हमें आता नहीं और झुकना हमने सीखा नहीं। शिक्षा रुकेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ छोटे देवड़ा में मिशन शिक्षा आगे बढ़ता रहेगा।



उन्होंने प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि आंधी-तूफान चाहे जितने आएं, पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं और शिक्षा की ज्योति जलाते रहेंगे।

सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने सभी छात्र-छात्राओं से नियमित रूप से ट्यूशन कक्षाओं में शामिल होकर पढ़ाई जारी रखने की अपील की है।

स्काई कंपनी की दीवार बनी किसान के खेत के लिए मुसीबत, 3 फीट तक भर रहा पानी

काला स्लैग और दूषित पानी खेत में घुसने से धान की फसल बर्बाद, 10-15 दिन तक जलभराव; किसान ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

जनता के गोठ/ओंकार साहू बलौदाबाजार:- औद्योगिक विकास की कीमत आखिर किसान कब तक चुकाएगा? ग्राम रिंगनी में स्काई कंपनी के आसपास स्थित किसान की कृषि भूमि जलभराव और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या से जूझ रही है। किसान डागालाल कोसरिया ने कंपनी पर खेत की प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता बंद करने और काला अपशिष्ट (स्लैग) खेत में पहुंचने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। किसान के अनुसार, कंपनी की बाउंड्रीवॉल से उसका खेत तीन तरफ से घिर गया है। कंपनी निर्माण से पहले खेत का बरसाती पानी प्राकृतिक रास्ते से पीछे स्थित तालाब तक पहुंचता था, लेकिन निर्माण के दौरान यह रास्ता बंद कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि बारिश के दौरान खेत में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है और निकासी नहीं होने से 10 से 15 दिनों तक पानी जमा रहता है। धान की फसल के साथ मिट्टी भी हो रही प्रभावित किसान का आरोप है कि कंपनी से निकलने वाला काला चूर्ण और स्पंज आयरन का स्लैग भी पानी के साथ खेत में पहुंच रहा है। इससे खेत की उपजाऊ मिट्टी प्रभावित हो रही है और धान की फसल सड़ने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि कई बार कंपनी प्रबंधन को फोटो और वीडियो के माध्यम से समस्या बताई गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ।

कलेक्टर से जांच और मुआवजे की मांग
पीड़ित किसान डागालाल कोसरिया ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर खेत के प्राकृतिक जल निकासी मार्ग को बहाल करने, दूषित अपशिष्ट का बहाव रोकने, तकनीकी जांच कराने और फसल एवं भूमि को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि एसडीएम और तहसीलदार सिमगा को भी भेजी गई है।

अब सवाल यह है कि औद्योगिक विकास के बीच किसान की खेती और उसकी आजीविका की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजरें टिकी हैं।

ग्राम झीट में सजेगा खो-खो का महाकुंभ: 27 से 29 नवंबर तक 'एडवेंचर ट्रॉफी संस्करण-3' का भव्य आयोजन, 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ
पाटन (दुर्ग): दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झीट में राज्य स्तरीय खेल जगत का एक बड़ा महासंग्राम सजने जा रहा है। एडवेंचर खो-खो क्लब झीट एवं समस्त ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 27 से 29 नवंबर तक राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता 'एडवेंचर ट्रॉफी संस्करण3' का भव्य आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय इस महामुकाबले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 20 प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें बालक वर्ग की 12 एवं बालिका वर्ग की 8 टीमें शामिल हैं। करीब 400 खिलाड़ियों के आगमन से ग्राम झीट तीन दिनों तक पारंपरिक खेल खो-खो के रोमांच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना से सराबोर रहेगा।



ग्रामीण प्रतिभाओं को तराश कर राष्ट्रीय मंच देना मुख्य ध्येय
एडवेंचर ट्रॉफी का यह तीसरा संस्करण ग्रामीण अंचल की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। आयोजन समिति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना और युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाकर खेलों के प्रति प्रेरित करना है। इस मंच के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों को न केवल अपनी गति और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय व उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी अनुभव भी प्राप्त होगा।

2014 से निरंतर राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर रहा क्लब
ग्राम झीट का एडवेंचर खो-खो क्लब वर्ष 2014 से जमीनी स्तर पर खो-खो खेल के संवर्धन और खिलाड़ियों के तकनीकी प्रशिक्षण में जुटा हुआ है। वर्तमान में इस क्लब के मैदान पर प्रतिदिन लगभग 100 बालक-बालिकाएं नियमित कड़ा अभ्यास करते हैं। क्लब की अनुशासित ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि प्रतिवर्ष यहां के 10 से 15 प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं।

मैदान से मंच तक व्यापक प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंध
प्रतियोगिता को भव्य और अनुशासित रूप देने के लिए गांव स्तर पर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। बाहर से आने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था, पौष्टिक भोजन, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा (मेडिकल टीम) तथा सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। मैदान को पेशेवर खेल मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, साथ ही दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्थित दीर्घा बनाई जा रही है। उत्कृष्ट खेल का मुजाहिरा करने वाली विजेता-उपविजेता टीमों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ियों को नकद राशि, स्मृति चिह्न और आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

बकावंड में 'बस्तर ओलंपिक 2026' का भव्य आगाज



प्रतिभाओं को तराशने में बस्तर ओलंपिक मील का पत्थर साबित होगा—जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ
जगदलपुर, / ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को सशक्त मंच प्रदान करने और युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासखंड स्तरीय 'बस्तर ओलंपिक 2026' का विधिवत शुभारंभ मंगलवार को बकावंड में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप शामिल हुईं।

समारोह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने कहा कि बस्तर अंचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, ÷बस्तर ओलंपिक केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार युवाओं को अपनी क्षमता साबित करने का एक सशक्त माध्यम है। यह आयोजन नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।÷

श्रीमती कश्यप ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास, आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। खेल से जुड़े युवा जीवन की हर चुनौती का सामना मजबूती से करने में सक्षम होते हैं।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण, खेल प्रशिक्षक तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

दीपाली सागर को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे परिजन, बाफना हाउस के सामने किया प्रदर्शन

रैली निकालकर लगाए 'फांसी के बदले फांसी दो' के नारे, प्रदर्शन के दौरान गमलों में तोड़फोड़ और शटर पर पथराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

भुजबल बघेल
जगदलपुर बकावंड जनता के गोठ। दीपाली सागर की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर मृतिका के परिजन और मोहल्लेवासी एकजुट होकर सड़क पर उतर आए हैं। मंगलवार को वार्ड से बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली और बाफना हाउस के सामने पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दीपाली को न्याय दिलाने की मांग करते हुए 'फांसी के बदले फांसी दो' के नारे लगाए।





दूसरे दिन भी जारी रहा परिजनों का धरना- दीपाली सागर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर परिजन 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक बाफना हाउस के सामने धरने पर बैठे रहे। इस दौरान मृतिका की मां की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बावजूद परिवार का आक्रोश कम नहीं हुआ। मंगलवार को एक बार फिर वार्डवासी घरों से रैली की शक्ल में दीपाली का पोस्टर लेकर बाफना हाउस पहुंचे और प्रदर्शन किया।

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग- प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपाली की मौत के मामले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच होनी चाहिए। घटना से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा किया जाए। परिजनों ने सुसाइड नोट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव- प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आक्रोशित भीड़ द्वारा दुकान के बाहर रखे गमलों में तोड़फोड़ की गई तथा दुकान के शटर पर पथराव भी किया गया। घटनाक्रम को देखते हुए बाफना हाउस के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोक जा सकें।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होंगी मौत की परिस्थितिया - पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान मृतिका के शरीर की तलाशी में कथित सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल उसकी पुरी विषयवस्तु सार्वजनिक नही की है फिलहाल दीपाली सागर की मौत का मामला जगदलपुर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

खबर-खास

शासकीय कार्यों में लापरवाही पर नप गए पटवारी मिथलेश वर्मा ,कलेक्टर श्री दुदावत ने किया निलंबित

कोरबा। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने पटवारी मिथलेश वर्मा, प.ह.नं. 40 भैरोताल, तहसील दर्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1673/भू.अ./पट.स्था./2026, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 के माध्यम से श्री वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी संधारित नहीं करने, कृषकों से संबंधित एग्रीस्टैक पंजीयन एवं बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि कार्य प्रारंभ नहीं करने, नक्शा बंटाकन और अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबित रखने तथा खरीफवर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य पीवी के माध्यम से नहीं किए जाने का उल्लेख था। श्री वर्मा ने नोटिस का जवाब 5 अक्टूबर 2026 को कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत किया। जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं पाए जाने के साथ ही उनके 13 अक्टूबर 2026 से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने की जानकारी मिली। इससे चक्रवात अर्नब के कारण हुई फसल क्षति के आकलन तथा धान खरीदी से पहले कृषकों की समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्य प्रभावित हुए। उक्त कृत्य को सेवा में व्यवधान तथा पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

मोबाइल विवाद में 17 वर्षीय छात्रा की संदेहास्पद मौत, जांच में जुटी पुलिस

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। दर्री थाना क्षेत्र की अयोध्या पुरी बस्ती में रहने वाली कक्षा 9वीं की 17 वर्षीय छात्रा सानिया बानो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना से पहले घर में मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। मृतका की पहचान अयोध्या पुरी बस्ती निवासी सानिया बानो के रूप में हुई है। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सानिया और उसके भाई के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी मां ने मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था। बताया जा रहा है कि इस बात से छात्रा नाराज थी। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलने पर दर्री पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों के बयान और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच शासन सख्तः कोरबा में पटवारी निलंबित, मचा हड़कंप,

कोरबा। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच शासन और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। शासकीय कार्यों में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तहसील दर्री में पदस्थ पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, प्रदेश के अन्य संभागों में भी पटवारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा संभाग के 819 और बिलासपुर संभाग के 259 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को भी निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है। कोरबा जिले में निलंबित किए गए पटवारी मिथलेश वर्मा भैरोताल पटवारी हल्का नंबर 40, तहसील दर्री में पदस्थ थे। प्रशासन के अनुसार, उनके द्वारा भू-अभिलेख नियमावली के तहत दैनिक डायरी का संधारण नहीं किया जा रहा था। किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन और बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का कार्य भी प्रारंभ नहीं किया गया था। इसके अलावा नक्शा बंटाकन, राजस्व अभिलेखों में सुधार तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य भी लंबित पाए गए थे। इन मामलों को लेकर कार्यालय कलेक्टर की भू-अभिलेख शाखा द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पटवारी मिथलेश वर्मा ने 5 अक्टूबर को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन प्रशासन ने उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। प्रशासन के मुताबिक, वे 13 अक्टूबर से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण चक्रवात अर्नब से हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं के निराकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से हड़ताल इधर, प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 अक्टूबर 2026 से जारी है।

कोरबा में दिसंबर से दौड़ेंगी 40 ई-बसें, सतरेंगा-मड़वारानी-कोसगाई तक जाएगी, 20 गांवों को होगा फायदा

कोरबा। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की कवायद अब हकीकत बनने वाली है। केंद्र सरकार से स्वीकृत 40 ई-बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। नगर निगम दिसंबर से इन बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। नई सेवा शुरू होने से न सिर्फ शहर बल्कि उपनगरीय इलाकों और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। केंद्र ने कोरबा जिले के लिए कुल 40 बसों को मंजूरी दी है, जिसमें 20 बड़ी ई-बसें और 20 ई-मिनी बसें शामिल हैं। नगर निगम ने इनके लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया है। सभी बसें रोजाना करीब 400 किलोमीटर तक शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में चलेंगी। एक बार फुल चार्ज होने पर एक बस लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी। पर्यटन स्थलों तक सीधी कनेक्टिविटी, 20 गांवों को होगा फायदा ई-बस सेवा का सबसे बड़ा फायदा पर्यटन स्थलों तक आवाजाही में मिलेगा। सतरेंगा, मड़वारानी और कोसगाई जैसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट तक अब सार्वजनिक परिवहन से पहुंचा जा सकेगा।

महादेव एपः सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण पर बोले दीपक बैज– 'भूपेश सरकार की 72 एफआईआर और लुकआउट नोटिस का परिणाम, लेकिन रवि उप्पल-शुभम सोनी कब आएंगे?'

कांग्रेस शासनकाल में दर्ज हुई थीं 72 एफआईआर और 500 से अधिक गिरफ्तारियां, गूगल प्ले से हटवाया था एपः पीसीसी चीफ

डबल इंजन सरकार में भी बेखौफचल रहे दर्जनों नए ऑनलाइन सट्टा एप, सोशल मीडिया पर खुलेआम हो रहे प्रचारः बैज

2023 चुनाव में भाजपा द्वारा रचे गए षड्यंत्र और उच्चस्तरीय संरक्षण की जांच कराने की उठाई मांग

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर, 03 नवंबरः महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे काफी विलंबित और अधूरी कार्रवाई करार दिया है। बैज ने कहा कि सौरभ चंद्राकर का भारत प्रत्यर्पण तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार द्वारा उठाए गए कड़े और वैधानिक कदमों का ही नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल सौरभ चंद्राकर को लाने से काम नहीं चलेगा, सिंडिकेट के अन्य प्रमुख चेहरों रवि उप्पल और शुभम सोनी को भारत कब लाया जाएगा?



'भूपेश सरकार ने दर्ज कराई थीं 72 एफआईआर और जारी कराया था लुकआउट नोटिस'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा कि महादेव एप के खिलाफ पहली एफआईआर से लेकर 72 एफआईआर दर्ज करने का ठोस काम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां और संपत्तियों की जब्ती भी तत्कालीन सरकार के दौरान ही की गई।

बैज ने कहा कि रायपुर पुलिस के आवेदन पर ही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कराया गया था तथा राज्य सरकार की पहल पर गूगल प्ले स्टोर से इस एप को प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान बनाने की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ही की थी।

'डबल इंजन सरकार में भी दर्जनों नए सट्टा पैनल खुलेआम सक्रिय'

भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय इस मुद्दे पर खूब दुष्प्रचार किया गया, लेकिन केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी पिछले तीन वर्षों में ऑनलाइन सट्टा पूरी तरह बंद क्यों नहीं हुआ? आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे एप्स के प्रचार खुलेआम चल रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि महादेव सिंडिकेट के तहत आज भी रेड्डी अन्ना, रेड्डी क्लब, एफ्बीबीईटी77, फेयरप्ले, सुपरविन, विनबज, लोटस 365, खेलोयार, स्काईएक्सचेंज और डायमंडएक्स जैसी दर्जनों सट्टा वेबसाइट्स और एप्स धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आती है, फिर भी इन पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लगाई जा सकी?

उच्चस्तरीय संरक्षण और जांच एजेंसियों की चुप्पी पर उठाए सवाल

दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर 2025 में इस मामले से जुड़े कई रसूखदार नाम सामने आए थे, जिनमें उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रमुख चेहरे शामिल थे। उन्होंने सवाल किया कि महादेव सट्टा सिंडिकेट को मिले कथित संरक्षण पर अब तक निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों की आड़ में राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। उस समय जारी किए गए कथित वीडियो और कैश बरामदगी के मामलों में संबंधित पहलुओं की निष्पक्ष जांच से केंद्रीय एजेंसियां बचती रही हैं। बैज ने कहा कि यह घोटाला अब देशव्यापी सिंडिकेट का रूप ले चुका है, जिसकी तह तक जाकर सभी वास्तविक साजिशकर्ताओं और संरक्षणदाताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

ऑपरेशन प्रहार के तहत धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बेचते 5 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। जिले में अवैध शराब की बिक्री और कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए धमतरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भखारा और अर्जुनी थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 59 पौवा देशी शराब और बिक्री की 1,650 रुपये नकद राशि जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 6,970 रुपये बताई गई है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देश पर अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में भखारा और अर्जुनी पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर घेराबंदी कर शराब बेच रहे पांच लोगों को पकड़ा। भखारा थाना क्षेत्र में कोलियारी गौठान के पास अछोटी निवासी शिवदयाल चेलक (59) को 24 पौवा देशी शराब और 410 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अर्जुनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें अर्जुनी निवासी डिगेश ध्रुव (24) के कब्जे से 10 पौवा शराब और 200 रुपये, संतराम सिन्हा (56) से 8 पौवा शराब और 310 रुपये, विष्णुराम यादव (58) से 9 पौवा शराब और 400 रुपये तथा टाकेश्वर उर्फ टाकू मीनपाल (40) से 8 पौवा शराब और 330 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) के तहत अलग-अलग पांच प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई तानाशाही, कम धान खरीदने के लिए हड़ताल खत्म नहीं कराना चाहती सरकारः कांग्रेस

50 पटवारियों के निलंबन और 'सर्विस इन ब्रेक' की धमकी को कांग्रेस ने बताया दमनकारी कदम

'पीवी ऐप' की तकनीकी खामियों से त्रस्त हैं पटवारी, तहसीलों में नामांतरण और बंटवारे के लाखों मामले अटके

सुशील आनंद शुक्ला बोले– रिकॉर्ड दुरुस्त न होने से हजारों किसान धान बेचने से हो जाएंगे वंचित

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर, 03 नवंबरः छत्तीसगढ़ में आंदोलनरत पटवारियों पर सरकार द्वारा की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के बजाय दमनकारी नीतियों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि 50 पटवारियों को निलंबित करना और काम पर न लौटने पर 'सर्विस इन ब्रेक' की धमकी देना सरकार के अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैये को उजागर करता है।



धान खरीदी से बचने के लिए हड़ताल टालने की साजिशः कांग्रेस- कांग्रेस संचार प्रमुख ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारियों की हड़ताल के चलते आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की तैयारियां बुरी तरह चरमरा गई हैं। किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है और न ही खसरा-खतौनी दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस हड़ताल को लंबा खींच रही है, ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण किसानों से कम से कम धान की खरीदी करनी पड़े।

'पीवी ऐप' की तकनीकी खामियां बनीं विवाद की जड़- सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि पटवारियों का विरोध पूरी तरह जायज है। राजस्व विभाग द्वारा उन पर अनिवार्य रूप से थोपे गए नए 'फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप' (PV App) में गंभीर तकनीकी कमियां हैं। तकनीकी बाधाएं: ऐप के माध्यम से डिजिटल सर्वे और जीपीएस फोटो अपलोड करने का नियम तो बना दिया गया, लेकिन लगातार सर्वर डाउन रहने और लोकेशन मिसमैच होने जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। व्यावहारिक दिक्कतें: खेत में खड़ी फसलों के भौतिक सत्यापन में तकनीकी अड़चनों के कारण काम ठप हो रहा है। पटवारी संघ ने आंदोलन से पहले ही शासन को इन समस्याओं से अवगत करा दिया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

नामांतरण-बंटवारे के लाखों मामले ठप, किसान परेशान- हड़ताल के प्रभाव का ब्योरा देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पटवारी प्रतिवेदन न मिलने के कारण प्रदेश के तहसीलदार और एसडीएम न्यायालयों में राजस्व के लाखों प्रकरण अटक गए हैं। धारा 115 के तहत लंबित सुधार प्रकरणों के अलावा फौती, नामांतरण और आपसी बंटवारे के लिए किसान दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते गिरदावरी और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किए गए, तो प्रदेश के हजारों पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह जाएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार दमनकारी रुख छोड़कर पटवारियों की जायज मांगों पर तत्काल सार्थक वार्ता करे और हड़ताल समाप्त कराकर किसानों को राहत दे।

बस्तर की तर्ज पर 2029 तक देश होगा नशा मुक्तः भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल बोले– तस्करों की संपत्ति कुर्क कर तोड़ी जा रही आर्थिक कमर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'नशा मुक्त भारत 2029' संकल्प का भाजपा ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ में पहली बार नशे के स्रोतों पर सीधा वार, सप्लायरों की अवैध संपत्तियां हो रहीं जब्त

वर्ष 2022 से 2026 के बीच 1.20 लाख किलो गांजा और 27.95 लाख नशीली दवाइयां की गईं नष्ट

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर, 03 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा देश को वर्ष 2029 तक नशा मुक्त बनाने के संकल्प का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्ययोजना के साथ केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर को नक्सलमुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, ठीक उसी तर्ज पर 2029 तक समूचे देश को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी हासिल किया जाएगा।



नक्सलवाद की तरह नशा भी समाज के लिए अभिशाप

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नक्सलवाद की भांति ही नशा भी देश के युवाओं और समाज के भविष्य को खोखला करने वाला गंभीर अभिशाप है। नक्सलवाद सीधे तौर पर हिंसा फैलाता है, जबकि नशा धीरे-धीरे पूरे परिवार और सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर देता है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह नक्सल नेटवर्क पर रणनीतिक प्रहार किया गया, उसी प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (ह्रष्टक्र) और राज्य की जांच एजेंसियां नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नशा मुक्त भारत का निर्माण ही 'विकसित भारत' के संकल्प की पहली और अनिवार्य शर्त है।

तस्करों की संपत्तियां कुर्क, जड़ पर सीधा प्रहार

अनुराग अग्रवाल ने रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ में एनडीपीएस (NDPS) मामलों में कार्रवाई का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। अब केवल स्थानीय सप्लायरों या पेडलर्स की गिरफ्तारी तक बात सीमित नहीं रहती, बल्कि जिस स्थान पर नशे की खेती या उत्पादन हो रहा है, वहां पहुंचकर उसे जड़ से खत्म किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्ती और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपराधी जेल की सजा काटने के बाद नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति का उपभोग न कर सके।

2022 से 2026 तक बड़े पैमाने पर नष्ट किए गए मादक पदार्थ

प्रदेश प्रवक्ता ने पिछले वर्षों में की गई कड़ी कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने 4,960 प्रकरणों में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया है, जिनमें शामिल हैं:

गांजा: 1,20,520 किलोग्राम से अधिक
नशीली दवाइयां/गोलियां: 27,95,574 नग
डोडा-चूरा: 4,195 किलोग्राम
चरस: 1,000 किलोग्राम
अफीम एवं ब्राउन शुगर: 3,334.57 ग्राम
हेरोइन: 1,011.82 ग्राम
एमडीएमए (स्ख्रष्ट्र): 9.5 ग्राम

अग्रवाल ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शासन-प्रशासन प्रदेश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के प्रति संकल्पित है।

सांसद विजय बघेल ने सुरक्षा अधिकारी गोविंद दीक्षित को सेवानिवृत्ति पर दी भावभीनी विदाई , उज्ज्वल भविष्य की कामना की

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग- दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल की सुरक्षा में सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे गोविंद दीक्षित के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर वृंदावन होटल इंटरनेशनल, दुर्ग में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने अपनी धर्मपत्नी रजनी बघेल एवं परिवार के साथ गोविंद दीक्षित को सेवानिवृत्ति की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया तथा उनके सेवाकाल की सराहना की। सांसद बघेल ने कहा कि वर्ष 2008 से 2026 तक लगभग 18 वर्षों की शासकीय सेवा में



दीक्षित ने पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सांसद की सुरक्षा व्यवस्था में उनका योगदान सदैव सराहनीय और स्मरणीय रहेगा। उन्होंने दीक्षित के स्वस्थ, सुखमय एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जीवन के इस नए पड़ाव में वे अपने परिवार के साथ सुखद समय बिताएं और अपने अनुभवों से समाज को भी लाभान्वित करें। समारोह में सांसद कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सहयोगी उपस्थित रहे। सभी ने गोविंद दीक्षित के साथ बिताए गए समय और उनके सेवाभाव को याद करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गोविंद दीक्षित ने सांसद विजय बघेल, रजनी बघेल एवं सांसद कार्यालय के समस्त सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह सौहार्दपूर्ण एवं भावुक वातावरण में संपन्न हुआ।

रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग का आगाजः गृह मंत्री अमित शाह ने किया 300 बेड वाले 'आर्टेमिस शांति हॉस्पिटल' का भव्य लोकार्पण

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर, 03 नवंबर: छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत के चिकित्सा परिदृश्य में मंगलवार को एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के विस्तार के रूप में राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर (पंडरी) में नव-स्थापित 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी 'आर्टेमिस शांति हॉस्पिटल' का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधिवत लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने फीता काटकर और लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर अस्पताल की अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं व मॉड्यूलर यूनिट्स का अवलोकन किया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर





दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल तथा रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी साक्षी बने। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब मेट्रो शहरों का रुख नहीं अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, आर्टेमिस शांति हॉस्पिटल की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय स्तर का उपचार मुहैया कराना है। हृदय रोग (कार्डियोलॉजी), कैंसर (ऑन्कोलॉजी), न्यूरोसाइंस, जटिल हड्डी एवं जोड़ रोग (ऑर्थोपेडिक्स), किडनी व यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तथा क्रिटिकल केयर जैसी गंभीर विधाओं के लिए अब मरीजों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा।

अत्याधुनिक तकनीक और 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं- अस्पताल को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुसज्जित किया गया है: 300 बेड एवं 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसः 30 से अधिक चिकित्सा एवं सर्जिकल विशेषज्ञताओं का विस्तृत नेटवर्क। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चरः विश्वस्तरीय मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (OT), जीवनरक्षक तकनीक से लैस अत्याधुनिक आईसीयू (ICU) और एडवांस इमेजिंग व डायग्नोस्टिक यूनिट्स। इमरजेंसी व ट्रॉमा बैकअपः दुर्घटना और आकस्मिक चिकित्सा के लिए 24 घंटे सातों दिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इमरजेंसी सेवाएं।

मध्य भारत के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता- लोकार्पण समारोह में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स एवं अपोलो टायर्स लिमिटेड के चेयरमैन ओंकार एस. कंवर ने कहाःआर्टेमिस का मूल ध्येय हमेशा से प्रत्येक मरीज को संवेदनशीलता और उच्चतम गुणवत्ता के साथ आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराना रहा है। दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकलकर मध्य भारत में यह हमारा पहला बड़ा विस्तार है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए हम आभारी हैं। इस अंचल के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा दीर्घकालिक संकल्प है। आर्टेमिस की प्रबंध निदेशक डॉ. देवलीना चक्रवर्ती ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मरीजों को उन्नत इलाज के लिए दूर-दराज के महानगरों की दौड़ न लगानी पड़े, इसी सोच के साथ यह सुपर स्पेशियलिटी ढांचा तैयार किया गया है। वहीं, आर्टेमिस शांति हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर डॉ. कमलेश अग्रवाल ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि संस्थान का लक्ष्य अनुभवी विशेषज्ञों, आधुनिक तकनीकों और रोगी-हितैषी माहौल के जरिए चिकित्सा गुणवत्ता और विश्वसनीयता के नए प्रतिमान स्थापित करना है।

पाटन विकासखंड के बच्चों ने अपने योग कौशल का प्रदर्शन किया

रायपुर। रायपुर में चतुर्थ छत्तीसगढ़ योगासन प्रतियोगिता यूथ एसोसिएशन के तत्वावधान में देवेंद्र नगर बुद्ध विहार रायपुर में आयोजित किया गया।

इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,जिसमें पाटन विकासखंड के बच्चों ने अपने योग कौशल का प्रदर्शन किया

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय अग्रवाल अध्यक्ष योग आयोग छत्तीसगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि ज्योति साहू योग प्रशिक्षक थी।

प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिलों से 250 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपने योग कौशल का प्रदर्शन किया।इस प्रतियोगिता में मर्रा से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें, सीनयर पुरुष (65+75) वर्ष आयु वर्ग मे ट्रेडिशनल योगासन प्रतियोगिता में श्री तुलाराम वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया सब जूनियर बालिका (6+12) आयु वर्ग रिदमिक पेयर में मोक्षिता



साहू,मानवी धीवर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बालक (6+12) आयु वर्ग आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में प्राथमेश कुमार वर्मा का शानदार प्रदर्शन रहा है

प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन को खेल के रूप में प्रोत्साहित करना तथा युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन एवं एकाग्रता की भावना का विकास करना है। आयोजन समिति ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन ज्योति कुंभारे,भीष्म कुमार साहू,चितरंजन साहू रश्मि वर्मा और गजेन्द्र ने किया व अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा है

खिलाड़ियों ने सफलता का श्रेय कोच धीरेन्द्र वर्मा को दिया।

खिलड़ियों को इस उपलब्धि पर डॉ. दिनेश चंद्रवंशी जिला आयुष अधिकारी दुर्ग, डॉ.अनीता साहू,भारत लाल ताम्रकार संतोष यादव खेल प्रभारी वि. ख पाटन,लाला राम वर्मा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।

एनआईटी रायपुर के 17वें दीक्षांत समारोह में 7 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' का शुभारंभः केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और सांसद बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर, 03 नवंबर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर का 17वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने बी.टेक, बी.आर्क, एम.टेक, एम.एससी, एमसीए और पीएचडी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह के साथ ही संस्थान में तकनीकी विकास को नई दिशा देने वाले 7 नव-स्थापित 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' का भी भव्य शुभारंभ किया गया।

सांसद के आग्रह पर मिला 'क्रिटिकल मिनरल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय



मंत्री जी. किशन रेड्डी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एनआईटी रायपुर में 'क्रिटिकल मिनरल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को मंजूरी दी है।

सांसद ने कहा कि संस्थान में शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिटिकल मिनरल्स और कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म सहित सभी सात उत्कृष्टता केंद्र देश के तकनीकी परिदृश्य को नई मजबूती प्रदान करेंगे। सामरिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने में यह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा।

छात्र जीवन और हॉस्टल के दिनों को किया याद

एनआईटी से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए सांसद भावुक नजर आए। उन्होंने कहाः

जब यह संस्थान केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, तब छात्र राजनीति और विभिन्न जनांदोलनों के दौरान हमने यहाँ के हॉस्टलों में रहकर दिन-रात बिताए हैं। यह देश का पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है जिसने खनन (माइनिंग) और मेटलर्जी की पढ़ाई शुरू की थी।

उन्होंने सादगी भरे दिनों का स्मरण कराते हुए गर्व जताया कि इस ऐतिहासिक संस्थान से निकले छात्र आज वैश्विक स्तर पर शीर्ष पदों पर नेतृत्व कर रहे हैं।

फाइलों में कैद न रहे रिसर्च, आमजन के जीवन में लाए सुधार- पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अपने अनुभवों का हवाला देते हुए सांसद अग्रवाल ने शोध कार्यों की सार्थकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रिसर्च का मूल्यांकन इस बात से नहीं होना चाहिए कि 200 या 500 रिसर्च पेपर्स फाइलों में दर्ज हो गए, बल्कि उसकी वास्तविक सफलता यह है कि उससे धरातल पर आम लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें विज्ञान, नवाचार और एआई की निर्णायक भूमिका होगी। उन्होंने युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे एआई जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग विध्वंस के बजाय मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण में करें।

देश-प्रदेश की प्रमुख विभूतियां रहीं उपस्थित- समारोह में सीएसआईआर (CSIR) की महानिदेशक डॉ. (श्रीमती) नल्लाथम्बी कलैसेल्वी, एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन.वी. रमना राव, शासी निकाय (BoG) के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, संस्थान के प्राध्यापकगण, देश-विदेश से आए शोधार्थी और बड़ी संख्या में उपाधि प्राप्तकर्ता छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

400 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी रोकने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण : वीरेन्द्र नामदेव

उच्च शिक्षा विभाग के 1 सितंबर 2026 के आदेश पर पुनर्विचार कर पेंशन व्यवस्था पूर्ववत बहाल करने की मुख्यमंत्री से मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा प्रभावित किए जाने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने तथा प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की व्यवस्था पूर्ववत बहाल करने की मांग की है।

नामदेव ने कहा कि इन महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को 12 अक्टूबर 2010 के विभागीय आदेश के आधार पर वर्षों से पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ मिल रहा था। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद जुलाई एवं अगस्त 2026 से पेंशन भुगतान प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई है। इससे प्रदेश के 400 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों में अनेक वरिष्ठ नागरिक 80 से 90 वर्ष की आयु के हैं। इस उम्र में पेंशन ही उनके जीवनयापन, दवाइयों और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का प्रमुख सहारा है। ऐसे समय में वर्षों से प्राप्त हो रही पेंशन रोक दिया जाना उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट और मानसिक परेशानी का कारण है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा, प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि नवीन वेतनमान अथवा संशोधित पेंशन निर्धारण के प्रस्ताव पर शासन का कोई निर्णय लंबित होना अलग विषय है, जबकि पूर्व से प्रचलित पेंशन व्यवस्था को प्रभावित करना अलग विषय है। दोनों को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की अर्जित सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा है, इसे किसी प्रकार की अनुकंपा नहीं माना जा सकता।

महासंघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उच्च शिक्षा विभाग के 1 सितंबर 2026 के आदेश पर पुनर्विचार कर उसे निरस्त अथवा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाए। शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की पूर्ववत पेंशन एवं ग्रेच्युटी व्यवस्था यथावत बहाल की जाए। जुलाई 2026 से रोकी गई पेंशन का तत्काल भुगतान प्रारंभ कर लंबित राशि का एरियर भी दिया जाए। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि इन प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष उच्च शिक्षा के विकास और विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में लगाए हैं। वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक असुरक्षा के हवाले करना न्यायोचित नहीं है।

पटवारियों की जायज मांगों पर दंडात्मक कार्यवाही के बजाय संवाद से समाधान करे सरकार : कमल वर्मा

PV ऐप की तकनीकी समस्याओं एवं वेतन विसंगति का निराकरण कर आंदोलन समाप्त कराने मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें

रायपुर/नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश में राजस्व पटवारियों की लंबित मांगों एवं PV ऐप की व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं के निराकरण के बजाय पटवारियों के विरुद्ध लगातार की जा रही दंडात्मक कार्यवाहियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

कमल वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों पर संवाद एवं सकारात्मक पहल के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए। PV ऐप की तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण तथा वर्षों से लंबित वेतन विसंगति का समाधान पटवारी संवर्ग की न्यायसंगत मांगें हैं। इन समस्याओं का निराकरण करने के बजाय बलौदाबाजार जिले में पटवारी संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य पटवारियों के स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस तथा महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन जैसी कार्यवाहियां किया जाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पटवारी पहले से ही डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, किसान पंजीयन, जनगणना, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण सहित अनेक महत्वपूर्ण शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में PV ऐप की जमीनी कठिनाइयों को समझे बिना कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना उनके मनोबल को प्रभावित करने वाला है। विभागीय कार्यवाहियों के कारण प्रदेशभर में भय एवं असंतोष का वातावरण निर्मित हो रहा है।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने कहा कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ



द्वारा 13 अक्टूबर 2026 से अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन को समाप्त कराने के लिए शासन को दमनात्मक रवैया अपनाने के बजाय संगठन के प्रतिनिधियों से तत्काल चर्चा करनी चाहिए। विभाग द्वारा पटवारियों की समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री तक प्रभावी ढंग से विषय प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है।

कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर ब्ल्क ऐप की तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं, वेतन विसंगति तथा पदोन्नति संबंधी लंबित मांगों का समयबद्ध निराकरण किया जाए। साथ ही पटवारियों के विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्यवाहियों की निष्पक्ष समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि संवाद के अभाव में उनके बीच भय का वातावरण निर्मित करना। फेडरेशन अपेक्षा करता है कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पटवारी संघ से सार्थक संवाद की पहल करेंगे तथा इस गतिरोध को समाप्त कर प्रदेश में राजस्व संबंधी शासकीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लेंगे।

बिना रेरा पंजीयन प्लॉट बेचने पर भिलाई के बालाजी बिल्डर्स पर 20 लाख का जुर्माना, सीजी रेरा की सख्त कार्रवाई

जनता के गोठ- रायपुर रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने रियल एस्टेट नियमों का खुला उल्लंघन करने वाले विकासकर्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भिलाई की फर्म मेसर्स बालाजी बिल्डर्स पर 20 लाख रुपये का भारी अर्थदंड अधिरोपित किया है।

बिना पंजीयन भूमि काटकर बेचे प्लॉट, खरीदारों से वसूली रकम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार, मेसर्स बालाजी बिल्डर्स के प्रोपराइटर जुगल किशोर तिवारी द्वारा भिलाई क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी।

धारा 3 का उल्लंघन, धारा 59 के तहत ठोका जुर्माना- सीजी रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भू-संपदा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी ऐसी परियोजना का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है...

खरीदारों के हितों से समझौता नहीं, बिल्डरों को सख्त हिदायत- प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि राज्य में रियल एस्टेट कारोबार केवल निर्धारित कानूनी मापदंडों के भीतर ही संचालित होगा।

पंडरी में आधी रात दुकानों पर चला हथौड़ाः फर्जी निगम कर्मी बनकर पहुंचे असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन पर साधा निशाना

4 दिन पहले थमाया था जर्जर का नोटिस, रात 2 बजे सब्बल-हथौड़े लेकर पहुंचे मजदूर

व्यापारियों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, FIR दर्ज न होने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुरः राजधानी के पंडरी स्थित जीवन बीमा मार्ग पर बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नगर निगम के फर्जी कर्मचारी बनकर पहुंचे असामाजिक तत्वों ने तीन पक्की दुकानों में सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ शुरू कर दी।





4 दिन पहले नोटिस, आधी रात को धावा

जानकारी के अनुसार, जीवन बीमा मार्ग स्थित तीन पक्की दुकानों पर महज 4 दिन पूर्व नगर निगम द्वारा 'जर्जर भवन' का हवाला देते हुए नोटिस चस्पा किया गया था।

बिल्डर लॉबी को लाभ पहुंचाने की साजिशः आकाश तिवारी

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन और पुलिस पर तीखा हमला बोला।

प्रमुख मांगें और 24 घंटे का अल्टीमेटम

नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:

उच्च स्तरीय जांचः महज 4 दिन के भीतर मजबूत इमारत को जर्जर बताकर आधी रात तोड़फोड़ कराने वाले अधिकारियों की शिनाख्त कर जांच बैठाई जाए।

आपराधिक मामला दर्जः रात में तोड़फोड़ करने वाले फर्जी कर्मचारियों और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे मौजूद मुख्य साजिशकर्ताओं पर लूट, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो।

पुलिस की भूमिका की पड़तालः व्यापारियों की शिकायत के बावजूद तत्काल कार्रवाई न करने वाले देवेंद्र नगर थाना प्रभारी व संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच हो।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोनः-9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com